mediaauditornews@gmail.com mediaauditor Epaperdainikmediaauditor.in mediaauditor वर्ष-29 अंक-245 पृष्ठ-8 मूल्य-3 रूपये

रीवा

05 सितम्बर 2025 शुक्रवार

दैनिक मीडिया ऑडीटर

दैनिक मीडियाऑडीटर

रीवा, सतना एवं मनेन्द्रगाढ़ से एक साथ प्रकाशित

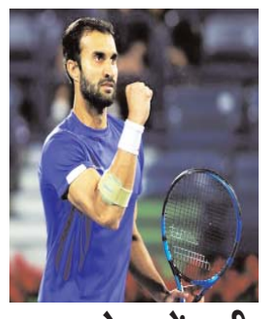

यूएस ओपन में यूकी @ पेज 7

एअर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान से टकराया पक्षी

विजयवाड़ा,एजेंसी। विजयवाड़ा से बंगलूरू जाने वाली एअर इंडिया एक्सप्रेस की एक उड़ान पक्षी से टकराने के बाद रद्द कर दी गई। एक एयरलाइन अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि उड़ान भरने के लिए रनवे पर टैक्सी करते समय एक चील विमान के अगले हिस्से से टकरा गई। एयरलाइन को उड़ान रद्द करनी पड़ी और यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ी। अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि पक्षी उड़ान भरने से पहले टकराया। यह तब हुआ, जब विमान रनवे पर टैक्सी कर रहा था।

केरल के विधायक राहुल ममकूटाथिल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

महिलाओं का पीछा करने और डराने-धमकाने का आरोप

तिरुवनंतपुरम,एजेंसी। केरल के विधायक राहुल ममकूटाथिल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उनके खिलाफ पीछा करने (स्टॉकिंग) और डराने-धमकाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है और यह रिपोर्ट कोर्ट में पेश की है। अपराध शाखा ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 78(2) के तहत पीछा करने और धारा 352 के तहत आपराधिक धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया है। इसके अलावा केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120 के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। यह प्राथमिकी बाल अधिकार आयोग की ओर से जारी नोटिस और राजनेताओं व सामाजिक कार्यकर्ताओं की नौ अन्य शिकायतों के आधार पर दर्ज की गई है।

पूरा मामला समझिए- ममकूटाथिल ने हाल ही में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जब मलयालम अभिनेत्री रिनी एन जॉर्ज ने एक प्रसिद्ध राजनीतिक दल के युवा नेता पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था। उसके बाद भाजपा और माकपा की युवा शाखा डीवाईएफआई ने विरोध प्रदर्शन किया था।

अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मामले में शिखर धवन से पूछताछ करेगी ईडी

नई दिल्ली,एजेंसी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन को अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े धन शोधन मामले की चल रही जांच में शामिल होने के लिए समन जारी किया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब कुछ दिन पहले ही ईडी ने पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना से पूछताछ की थी।सूत्रों ने बताया कि धवन को इस अवैध सट्टेबाजी मामले में पूछताछ के लिए गुरुवार को एजेंसी के दिल्ली मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। यह मामला 1एक्स-बीईट नामक ऐप से जुड़ा है। उन्होंने बताया कि धवन सुबह 11 बजे एजेंसी के दफ्तर पहुंचे हैं।

पंजाब-हरियाणा में बाढ़, 48 की मौत,हिमाचल के कुल्लू में लैंडस्लाइड

दिल्ली में यमुना का पानी सड़कों पर, लाईओवर धंसा

चंडीगढ़/दिल्ली/शिमला,एजेंसी। पंजाब के सभी 23 जिलों में बाढ़ आ गई है। 1,655 गांवों में 3.55 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। राज्य में सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की छुट्टियां 3 सितंबर से बढ़ाकर 7 सितंबर कर दी गई हैं। 1 अगस्त से 3 सितंबर तक बाढ़ में 37 लोगों की मौत हुई है। पठानकोट में 3 लापता हैं।

हरियाणा के कई इलाके भी बाढ़ में डूबे हैं। राज्य में 11 लोगों की मौत हुई है। हिसार, पंचकूला, अंबाला और रोहतक में सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली से पानी छोड़ने से फरीदाबाद में यमुना खतरे के निशान तक पहुंच गई है।

इधर, दिल्ली में यमुना का पानी शहर के अंदर घुस गया है। गुरुवार सुबह मॉनेस्ट्री मार्केट में

सड़क पर एक फीट तक पानी भर गया। मयूर विहार फेज-1 के पास बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बने राहत शिविरों में यमुना का पानी भर गया। अलीपुर में नेशनल हाईवे-44 पर फ्लाईओवर का एक हिस्सा धंस गया।

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में गुरुवार सुबह लैंडस्लाइड में दो घर ढह गए। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। 6 लोग अंदर फंस गए हैं। कुल्लू में बुधवार को भी लैंडस्लाइड हुई थी। मलबे में दबे एक NDRF जवान को 24 घंटे बाद आज रेस्क्यू किया गया। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू की गड़सा घाटी में बादल फटने के बाद नदी में बहकर आई लकड़ियां।

सुप्रीम कोर्ट में बाढ़-बारिश से हालात खराब होने पर गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और पंजाब को नोटिस भेजा है और तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि पहाड़ियों में पेड़ों की अवैध कटाई की इसलिए प्रकृति हमसे बदला ले रही है। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के पानी में पहाड़ियों से बहकर आई लकड़ी की बड़ी संख्या में लकड़ियों के लट्ठों के वीडियो का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है।

हिमाचल ने केंद्र से रेस्क्यू को मांगे 5 हेलिकॉप्टर

भरमौर में फंसे 700 श्रद्धालु; 4 के शव कुगती में

चंबा,एजेंसी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में मणिमहेश यात्रा पर निकले 4 श्रद्धालुओं की डेडबॉडी कुगती ट्रेक पर फंसी हुई है। इन्हें निकालने के लिए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने डीएसपी खजाना राम की नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की है। इस दल में पुलिस, होमगार्ड, माउंटेनियरिंग दल और स्थानीय लोगों को शामिल किया गया है। स्थानीय प्रशासन 4 दिन से इन शवों को भरमौर तक लाने की कोशिश कर रहा है। मगर निरंतर हो रही बारिश और खराब मौसम इसमें बाधा उत्पन्न कर रहा है। वहीं भरमौर में अभी भी लगभग 700 मणिमहेश श्रद्धालु फंसे हुए हैं। राज्य सरकार ने इन्हें निकालने के लिए एयरफोर्स से पांच से छह हेलिकॉप्टर मांगे हैं।

कृषि मंत्री शिवराज बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंचे

किसानों से फसलों का हाल जान रहे; बोले- 2 केंद्रीय टीमें नुकसान का आकलन कर रहीं

अमृतसर, एजेंसी। बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात का जायजा लेने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब दौरे पर हैं। अमृतसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद केंद्रीय मंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्र अजनाला पहुंचे। यहां वह किसानों से मिले। किसानों ने उन्हें खराब हुई फसलों के बारे में बताया। उनके साथ कांग्रेस सांसद गुरजीत औजला और भाजपा जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग मौजूद रहे। इससे पहले केंद्रीय मंत्री से अमृतसर हवाई अड्डे पर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने मुलाकात की और 5 राज्यों में नुकसान की रिपोर्ट सौंपी। इनमें अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर, तरनतारन और फिरोजपुर शामिल हैं। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें पंजाब भेजा है, ताकि वह जमीनी हालात का सीधा आकलन कर सकें। इसके बाद वह बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा करने रवाना हुए। शिवराज ने कहा कि पंजाब हमेशा देश की सेवा में सबसे आगे रहा है। आज जब राज्य बाढ़ की त्रासदी से जूझ रहा है, तब केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार पंजाब के साथ खड़ी है। कृषि मंत्री ने बताया कि केंद्र की दो टीमें पहले ही पंजाब पहुंच चुकी हैं। ये टीमें अलग-अलग विभागों के अधिकारियों के साथ नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट तैयार करेंगी, जिसे प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा।

बिना पूर्व भुगतान के दुर्घटना पीड़ितों का तुरंत इलाज करें, वरना लगेगा जुर्माना, अस्पतालों को आदेश

बंगलूरू, एजेंसी। कर्नाटक सरकार ने सभी चिकित्सा संस्थानों और डॉक्टरों को याद दिलाया कि वे किसी भी दुर्घटना पीड़ित का तुरंत उपचार करें और उनसे किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान (एडवांस पेमेंट) न मांगें। एक सरकारी आदेश में बुधवार को यह निर्देश दिया गया।

सरकार ने कहा, यह जरूरी है कि कानून और राज्य में चल रही योजनाओं को लागू करने वाली एजेंसियों और आम लोगों को एक बार फिर बताया जाए कि दुर्घटना पीड़ितों का इलाज बिना देरी और बिना एडवांस पेमेंट के किया जाना अनिवार्य है। कर्नाटक निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान अधिनियम, 2007 के तहत, दुर्घटना पीड़ित की परिभाषा केवल सड़क हादसों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जलने, जहर खाने या आपराधिक हमलों जैसी स्थितियां भी शामिल हैं।

नियम के उल्लंघन पर अस्पताल को लगेगा एक लाख का जुर्माना: आदेश में कहा गया, जब भी कोई ऐसा दुर्घटना पीड़ित अस्पताल में आता है या लाया जाता है, तो उसका आपात स्थिति में तत्काल उपचार किया जाना चाहिए अग्रिम भुगतान की मांग नहीं की जानी चाहिए। अगर कोई अस्पताल इस नियम का उल्लंघन करता है, तो धारा 19 (5) के तहत उस पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

कानून के अनुसार आवश्यक उपचार प्रदान करना जरूरी

सरकार ने कर्नाटक गुड समेरिटन एंड मेडिकल प्रोफेशनल एक्ट, 2016 का भी हवाला देते हुए कहा कि हर अस्पताल को मुफ्त मेडिकल स्क्रीनिंग, फर्स्ट-एड और आवश्यक उपचार प्रदान करना अनिवार्य है, ताकि मरीज की स्थिति में सुधार हो सके। अगर किसी अस्पताल में इलाज की सुविधाएं नहीं हैं, तो उसे पहले मरीज को स्थिर करना होगा और फिर दूसरी जगह रेफर करना होगा, साथ ही चिकित्सा दस्तावेज भी देना होगा। इसके अलावा, सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 187 का भी हवाला देते हुए कहा कि नियमों का पालन न करने पर तीन महीने की जेल या 500 रुपये जुर्माना और दोबारा अपराध करने पर छह महीने की जेल या 1,000 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है।

हादसा पीड़ित को सात दिनों तक नकदी रहित चिकित्सा सुविधा

राज्य सरकार ने बताया कि सड़क हादसा पीड़ितों के लिए नकदी रहित (कैशलेश) उपचार योजना, 2025 के तहत अब हर सड़क हादसे के पीड़ित को 1.5 लाख रुपये तक की नकदी रहित चिकित्सा सुविधा सात दिनों तक दी जाएगी। इसके लिए राज्य सड़क सुरक्षा परिषद नोडल एजेंसी होगी और खर्च की भरपाई मोटर वाहन दुर्घटना फंड से की जाएगी। सरकार पहले से ही 48 घंटे तक की नकदी रहित चिकित्सा योजना चला रही है, जिसमें सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और एसएएसटी सूचीबद्ध अस्पतालों में 76 जीवन रक्षक सेवाएं कवर की गई हैं।

आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि हर पंजीकृत डॉक्टर और हर अस्पताल को तुरंत प्राथमिक उपचार देना और मरीज को स्थिर करना अनिवार्य है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर नियम के अनुसरा सजा लागू होगी।

5 कारोबारियों की मौत, ट्रक ने 25 मीटर तक घसीटा,पटना में 100 की स्पीड में ट्रक में घुसी कार

गैस कटर के काटकर निकाली बॉडी

पटना, एजेंसी। पटना में सड़क हादसे में 5 कारोबारियों की मौत हुई है। बुधवार रात 1 बजे कारोबारियों की कार चलते ट्रक में पीछे से जा घुसी। हादसा परसा बाजार थाना के महोली फ्लाई ओवर के नीचे हुआ है।

हादसा इतना भीषण था कि कार ट्रक के अंदर घुस गई। ट्रक के ड्राइवर को इसका पता भी नहीं चला। वह कार को घसीटते हुए 25 मीटर तक दूर तक चला गया।

सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। गैस कटर से कार को काटकर सभी शवों को निकाला गया।

मरने वालों में गोपालपुर के 50 साल के राजेश कुमार, 38 साल के संजय कुमार, सिपारा के 38 साल के कमल किशोर, 35 साल के प्रकाश चौरसिया और मुजफ्फरपुर के 30 साल के सुनील कुमार शामिल हैं।

सभी लोग फतुहा से परसा

बाजार होते हुए पटना की ओर आ रहे थे। इसी बीच फ्लाई ओवर के नीचे आगे जा रही ट्रक को कार ने पीछे से टक्कर मार दी। पांचों ने हादसे से कुछ घंटे पहले एक साथ में सेल्फी ली थी।

टक्कर के बाद तेज धमाका हुआ : प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर के बाद जोरदार धमाका हुआ और कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परसा बाजार थाना पुलिस और पटना सदर के DSP रंजन कुमार मौके पर पहुंचे। पुलिस को कार में फंसे शवों को निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। कार को गैस कटर से काटकर शवों को बाहर निकाला गया और पोस्टमॉर्टम के लिए PMCH भेजा गया।

कार के अंदर ही पांचों की मौत हुई

बताया जा रहा है कि यह सभी कारोबारी फतुहा से पटना वापस लौट रहे थे। इसी दौरान परसा बाजार थाना क्षेत्र के सुईया मोड़ के पास ये हादसा हुआ। पूरी कार ट्रक के अंदर घुस गई। हादसे में कार में बैठे 5 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। परसा बाजार थाना प्रभारी मेनका रानी ने बताया कि मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई। यह सभी गाड़ी के अंदर फंसे थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। ग्रामीणों की मदद से सभी लोगों को बाहर निकाल कर पटना के PMCH में भेजा गया है।

आतंकी फंडिंग केस में शबीर शाह को राहत नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से किया इनकार

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कश्मीरी अलगाववादी नेता शबीर अहमद शाह की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। शाह ने आतंकी फंडिंग केस में स्वास्थ्य कारणों से राहत की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसे ठुकरा दिया। हालांकि, शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। शाह दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दे रहे हैं जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया था। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप नाथ की पीठ के सामने वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्वेस ने शाह की ओर से दलीलें पेश कीं। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता गंभीर रूप से बीमार हैं और उन्हें तुरंत अंतरिम जमानत की जरूरत है। इस पर जस्टिस नाथ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या आज ही उन्हें छोड़ देना चाहिए?

अदालत ने साफ किया कि अंतरिम जमानत नहीं दी जाएगी और मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी।

हाईकोर्ट ने भी नकारा था जमानत का अनुरोध : दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 जून को शाह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि उनके दोबारा गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन इसका दुरुपयोग भड़काऊ भाषण या हिंसा के लिए नहीं किया जा सकता।

गंभीर आरोपों में गिरफ्तारी

शबीर शाह को एनआईए ने 4 जून 2019 को गिरफ्तार किया था। इससे पहले 2017 में एनआईए ने आतंकी फंडिंग केस में 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इन पर आरोप था कि ये पत्थरबाजी, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश में शामिल थे। शाह पर अलगाववादी आंदोलन को समर्थन देने, आतंकियों के परिवारों को शहीद बताकर सम्मानित करने, हवाला और एलओसी व्यापार से पैसा जुटाकर उसे हिंसक गतिविधियों में लगाने का आरोप है।

'घर में नजरबंदी' की मांग भी ठुकराई गई : हाईकोर्ट ने शाह की उस वैकल्पिक मांग को भी ठुकरा दिया था जिसमें उन्होंने गंभीर आरोपों को देखते हुए घर में नजरबंदी का विकल्प रखा था।

संघ की समन्वय बैठक :

शताब्दी वर्ष की तैयारियों और वर्तमान परिस्थितियों पर होगी चर्चा

जोधपुर, एजेंसी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की अखिल भारतीय समन्वय बैठक शुक्रवार से जोधपुर में आरंभ होगी। तीन दिनों (5, 6 और 7 सितंबर) तक चलने वाली इस बैठक में भाजपा, विश्व हिन्दू परिषद, मजदूर एवं किसान संघ सहित संघ से जुड़े विविध संगठन भाग लेंगे। बैठक में संघ के शताब्दी वर्ष की तैयारियों और देश की वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा होगी।आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने गुरुवार को यहां पत्रकारों को इसकी जानकारी दी। उनके साथ सह प्रचार प्रमुख प्रदीप जोशी भी मौजूद रहे।

आंबेकर ने बताया कि यह बैठक प्रतिवर्ष होती है। पिछली बैठक केरल के पालक्काड में आयोजित हुई थी। इस बार जोधपुर की बैठक में लगभग 320 कार्यकर्ता शामिल होंगे। इनमें 32

विविध संगठनों 249 से अधिक प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। बैठक का शुभारंभ शुक्रवार सुबह 9 बजे होगा।

बैठक में सरसंघचालक मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले मार्गदर्शन देंगे। सभी सह सरकार्यवाह भी मौजूद रहेंगे। साथ ही, प्रत्येक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन मंत्री और अन्य पदाधिकारी भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि संघ से जुड़े संगठन समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में कार्यरत हैं। वे शिक्षा, सेवा, सामाजिक सद्भाव और जनजागरण जैसे क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

आंबेकर ने स्पष्ट किया कि यह बैठक निर्णय लेने वाली नहीं होती, बल्कि समन्वय बढ़ाने का मंच है। संगठन यहां अपने-अपने कार्य का विवरण और आकलन प्रस्तुत करते हैं। वे देश की परिस्थिति और समाज की आवश्यकताओं को देखते हुए अपने सुझाव साझा करते हैं। वहीं निर्णय संगठन अपनी कार्यकारिणी बैठकों में लेते हैं। संगठनों की कार्यपद्धति पर प्रकाश डालते हुए आंबेकर ने कहा कि संघ से जुड़े संगठन समाज के विविध क्षेत्रों में कार्यरत हैं। वे क्षेत्र से जुड़ी कमियों और अपेक्षाओं का अध्ययन करते हैं। साथ ही वे समाधान सुझाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर सरकार तक अपनी बात रखते हैं और जरूरत पड़ने पर आंदोलन भी करते हैं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य समाज में अपेक्षित परिवर्तन और देशहित में कार्य करना है।

इस बार की बैठक विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आगामी विजयदशमी पर्व पर संघ अपने 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। बैठक में शताब्दी वर्ष की योजनाओं पर भी चर्चा होगी। नागपुर से शताब्दी कार्यक्रम का आरंभ होंगे। इसके बाद हिन्दू सम्मेलन, गृह संपर्क और सामाजिक सद्भाव की बैठकें होंगी।

सरकार 24 रुपये किलो बेचेगी प्याज, जोशी ने मोबाइल वैन को दिखाई हरी झंडी

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने गुरुवार को यहां एनसीसीएफ, नैफेड और केंद्रीय भंडार की मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर 24 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज की खुदरा बिक्री का शुभारंभ किया।उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्रह्लाद जोशी ने 24 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सब्सिडी वाले प्याज बेचने वाली वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। फिलहाल नई दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद में प्याज की खुदरा बिक्री आज से शुरू हो गई। इस कार्यक्रम के साथ ही सरकारी बफर स्टॉक से प्याज की लक्षित और संतुलित मात्रा में आपूर्ति शुरू हुई, ताकि उपभोक्ताओं को यह आवश्यक सब्जी किफायती दामों पर उपलब्ध हो सके।इस अवसर पर मंत्री जोशी ने कहा कि सरकार किसानों और उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखना भारत सरकार की प्राथमिकता है। मूल्य स्थिरीकरण उपायों के माध्यम से विभिन्न प्रत्यक्ष हस्तक्षेपों ने हाल के महीनों में महंगाई दर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जुलाई 2025 में सामान्य खुदरा महंगाई दर 1.55 फीसदी रही, जो लगभग आठ वर्षों में सबसे कम है। बफर स्टॉक से प्याज का संतुलित और लक्षित निपटान, खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और स्थिर मूल्य व्यवस्था बनाए रखने के सरकार के प्रयासों का एक अभिन्न अंग है।

सीबीएसई और एनसीबी मिलकर स्कूलों को बनाएंगे नशामुक्त

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने स्कूलों को नशामुक्त करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसके लिए सीबीएसई और एनसीबी ने बुधवार को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए है। इस एमओयू का उद्देश्य स्कूलों को नशामुक्त करने और मादक पदार्थों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। दोनों संस्थान नशीली दवाओं के सेवन के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने में सहयोग करेंगे। इसके बाद एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें देशभर से 500 से अधिक प्राचार्य, परामर्शदाता और वेलनेस शिक्षकों ने हिस्सा लिया।सीबीएसई के द्वारका स्थित कार्यालय में हुए इस समझौता कार्यक्रम में सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और एनसीबी के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने हस्ताक्षर किए। कार्यक्रम में सीबीएसई सचिव हिमांशु गुप्ता, व दोनों संस्थानों के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर सीबीएसई चेयरमैन राहुल सिंह ने कहा कि बोर्ड छात्रों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है और शिक्षकों अभिभावकों और स्कूलों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएगा। एनसीबी के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने इस अवसर पर नशामुक्ति की दिशा में शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। इस एमओयू के तहत समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही शिक्षकों और परामर्शदाताओं के लिए प्रशिक्षण, नशीली दवाओं की रोकथाम पर ई-मॉड्यूल और सामुदायिक जागरूकता पहल आयोजित की जाएंगी।

भारतीय संस्कृति और मूल्यों को बचाने के लिए आवाज उठाएं युवा : रेखा गुप्ता

नई दिल्ली, एजेंसी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने युवाओं से भारतीय संस्कृति और मूल्यों को बचाने के लिए आवाज उठाने का आह्वान किया है। इस्कॉन के कॉन्टेंट क्रिएटर्स समिट में उन्होंने कहा कि जब संस्कृति और सभ्यता पर आंच आए तो चुप न रहें। सीएम ने कंटेंट क्रिएटर्स और युवाओं को राष्ट्र और संस्कृति से जोड़ने का संदेश दिया।

लोधी रोड पर जोरा दिल्ली कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कॉन्टेंट क्रिएटर्स समिट 2025 में 500 से अधिक डिजिटल क्रिएटर्स ने भारतीय संस्कृति, वेलनेस और पर्यटन को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री ने युवाओं से कहा, देश को उनकी जरूरत है। जब कोई हमारी संस्कृति पर उंगली उठाए तो जवाब देना होगा। प्रभु कृष्ण के अनुयायी होने के नाते हमें गलत को गलत कहने का साहस दिखाना होगा। मोबाइल और कंप्यूटर के जरिये लड़ी जाने वाली लड़ाई भी उतनी ही अहम है, जितनी सरहद पर। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण भूपेंद्र यादव, दिल्ली के पर्यटन और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा भी मौजूद रहे।मंत्री ने कहा कि युवाओं की मुखर आवाज को राष्ट्र और संस्कृति से जोड़ना समय की जरूरत है। इस तरह के आयोजन नई पीढ़ी को भारतीय मूल्यों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। जब युवा संस्कृति और अध्यात्म के साथ जुड़ेंगे, तभी विकसित भारत का सपना पूरा होगा। समिट में इस्कॉन ने घोषणा की कि 12 अक्तूबर को दिल्ली में 15,000 युवाओं के साथ मेगा यूथ इवेंट होगा। ये नशा मुक्त भारत और विकसित भारत थीम पर आधारित होगा।

जयंती पर दादाभाई नौरोजी को दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली, एजेंसी। दादाभाई नौरोजी की जयंती के अवसर पर गुरुवार को संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह, राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने दादाभाई नौरोजी को श्रद्धासुमन अर्पित किए।

लोकसभा सचिवालय के मुताबिक ÷द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया÷ के रूप में विख्यात दादाभाई नौरोजी को 1892 में हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले ब्रिटिश-भारतीय होने का गौरव प्राप्त है। ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध दादाभाई भारतीय स्वतंत्रता की मांग को दृढ़ता से रखने वाले राष्ट्रवादी नेताओं में से एक थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में दादाभाई नौरोजी की अग्रणी भूमिका का स्मरण करते हुए तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर ने 13 मार्च 1954 को संसद के केन्द्रीय कक्ष में उनके चित्र का अनावरण किया था।

दिल्ली सचिवालय के पास पहुंचा यमुना का पानी... राहत शिविर भी डूबे 208 मीटर के करीब जलस्तर

नई दिल्ली, एजेंसी। यमुना में लगातार बढ़ रहे जलस्तर से देश की राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बाढ़ के कारण हजारों लोग बेघर हो गए हैं। अब शहर के भीतरी हिस्सों में भी पानी भरने का खतरा बढ़ गया है। वहीं, हथिनीकुंड बैराज से बुधवार सुबह से लेकर रात तक छोड़े जा रहे पानी को दिल्ली आते देखकर ये साफ है कि पानी जल्द कम नहीं होगा। देर रात यमुना का जलस्तर 207.40 मीटर तक पहुंच गया था। केंद्रीय जल आयोग ने सूचना जारी की है कि दिल्ली में पानी और बढ़ सकता है।

इससे आशंका है कि दिल्ली में यमुना का जलस्तर 208 मीटर तक पहुंच सकता है। यदि ऐसा होता है तो 2023 की बाढ़ की तरह आउटर रिंग रोड और कश्मीरी गेट आईएसबीटी तक पानी पहुंचने के आसार हैं। इससे दिल्ली में न केवल आवागमन बाधित हो सकता है बल्कि बड़े पैमाने पर जनजीवन प्रभावित होने का खतरा भी है। मयूर विहार-फेज 1 के पास बनाए गए राहत शिविरों में पानी वहीं, दिल्ली में लगातार बारिश और यमुना नदी में उफान की वजह से मयूर विहार-फेज 1 के पास बनाए गए राहत शिविरों में पानी भर गया है। दिल्ली के सिविल लाइंस में बेला रोड

पर उफनती यमुना नदी का पानी घुसने से वाहन डूब गए, इमारतें जलमग्न हो गईं। निचले इलाकों में रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा बाढ़ की आशंका को देखते हुए यमुना नदी के पास निचले इलाकों में रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है। दिल्ली में लोहा पुल और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है।

निगमबोध घाट डूबा, अंतिम संस्कार पर रोक यमुना के जलस्तर का असर राजधानी के सबसे बड़े श्मशान घाट निगमबोध पर भी पड़ा है। बुधवार शाम को पूरी तरह बाढ़ की चपेट में आने से यहां अंतिम संस्कार की प्रक्रिया रोक दी गई है। घाट परिसर में कई फीट तक पानी भर गया है। यमुना का पानी बहकर रिंग रोड तक पहुंच गया है। प्रशासन ने निगमबोध घाट को बचाने के लिए कई प्रयास किए। यमुना की ओर मिट्टी भरकर बोरे लगाकर पानी को रोकने की कोशिश की गई लेकिन पानी के बढ़ते दबाव के आगे यह प्रयास नाकाम साबित हुए। घाट की एक तरफ दीवार का कुछ हिस्सा भी टूट गई जिससे पानी का प्रवाह और तेज हो गया। बाढ़ नियंत्रण विभाग और एमसीडी की टीमें मौके पर मौजूद हैं और हालात पर नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के लिए मुसीबत दिल्ली के वजीराबाद में यमुना का बढ़ता जलस्तर पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के लिए मुसीबत बन गया है। घरों में पानी भरने से लोगों को सिग्नेचर ब्रिज के पास शरण लेनी पड़ रही है। लोगों का आरोप है कि शासन-प्रशासन ने उनकी सुध नहीं ली और न ही टेंट या अन्य बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की गई। भारी बारिश ने उनकी मुश्किलों को और बढ़ा दिया है।

कीचड़, पानी और ठंड के बीच खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर ये परिवार अपने आशियाने को खोने के डर से सहमे हुए हैं। यही नहीं रात में वर्षों की मेहनत की कमाई और घर के सामान को बचाने के लिए रातभर जागने को मजबूर हैं। शरणार्थी राहुल सिंह ने बताया कि घरों तक पानी पहुंच गया है। प्रशासन ने न टेंट दिए और न ही खान-पान की ठीक व्यवस्था है। बारिश होने से बच्चे बीमार हो रहे हैं। बाढ़ के खतरे के बीच घर की चिंता ज्यादा सता रही है। हमने इतनी मुश्किल से आशियाना बनाया था। अन्य शरणार्थी ने बताया कि हम पाकिस्तान से भागकर यहां शरण लेने आए थे, लेकिन अब विस्थापित हो गए। कोई टेंट नहीं सिर्फ खुले आसमान तले रहना पड़ रहा है। भोजन और पानी की कमी से कई तरह की परेशानियां हो रही हैं।

मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट, जानें क्या बोलीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता

दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार के द्वारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स कार्उंसिल की 56वीं बैठक के बाद बीते दिन यानी बुधवार को जीएसटी से जुड़े कई बड़े बदलाव सामने आए। जिसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जीएसटी को लेकर कहा कि मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहती हूं, उन्होंने देश के आम नागरिक को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। इतनी बड़ी राहत जिससे न सिर्फ आम आदमी को फायदा होगा बल्कि कई क्षेत्रों में दी गई राहत के लिए जनता प्रधानमंत्री का धन्यवाद करती है। उन्होंने कहा कि जीएसटी में किए गए बदलाव, जैसे दो स्लैब (5त्न और 18त्न) और आवश्यक वस्तुओं पर शून्य कर, आम नागरिकों, स्वास्थ्य, बीमा,

इलेक्ट्रॉनिक्स, शिक्षा और व्यवसायों के लिए बड़ी राहत लाएंगे। यह कदम छोटे और बड़े व्यवसायों को स्थिरता प्रदान करेगा और एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।इसके अतिरिक्त, सीएम गुप्ता ने पहले भी व्यापारियों के लिए 1600 करोड़ रुपये के लंबित जीएसटी रिफंड को दीपावली से पहले अदा करने की घोषणा की थी, जिससे दिल्ली के व्यापारियों को आर्थिक राहत मिलेगी। साथ ही, दिल्ली जीएसटी अधिनियम में संशोधन और एमनेस्टी स्कीम जैसे कदमों से करदाताओं को लाभ हुआ है।

जीएसटी कार्उंसिल की 56वीं बैठक में वित्त मंत्रालय ने गहन मंथन के बाद आईपीएल जैसे खेल आयोजनों के टिकट पर जीएसटी, तंबाकू-सिगरेट जैसे उत्पादों पर लगने वाले टैक्स, बीमा पर कर की दरों में बदलाव जैसे अहम फैसले लिए।

ड्रग्स सप्लाई में नाइजीरियाई और एक महिला समेत छह गिरफ्तार, अफ्रीकी नागरिक ने किया सिंडिकेट का खुलासा

दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने ड्रग्स सप्लाई करने वाले दो नाइजीरियाई नागरिक और महिला समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को दिल्ली, ग्रेनो और बेंगलुरु से पकड़ा गया है। इनके कब्जे से लगभग 21 करोड़ रुपये के मूल्य का 7 किग्रा मेथमफेटामाइन बरामद की गई है। अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त हर्ष इंदौरा ने बताया, 19 जुलाई को एक सूचना मिली कि केरल में एनडीपीएस के विभिन्न मामलों में वांछित सुहैल दिल्ली से बेंगलुरु, केरल और दक्षिण भारत के विभिन्न हिस्सों में प्रतिबंधित मादक पदार्थों की सप्लाई करता है। टीम ने दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के एक बीएनबी गेस्ट हाउस से केरल के कन्नूर निवासी सुहैल और सुजिन को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 5950 ग्राम मेथमफेटामाइन बरामद किया गया।जांच में पता लगा कि आरोपी व्हाट्सएप पर बातचीत के लिए नाइजीरिया का नंबर का इस्तेमाल कर रहा था। इसके बाद पुलिस ने दिल्ली के छतरपुर इलाके में रहने वाले अफ्रीकी नागरिक टोबी डेको को गिरफ्तार कर लिया। इससे 64 ग्राम मेथामफेटामाइन बरामद किया गया। उसने बताया कि वह सुहैल को ड्रग्स की सप्लाई करता है।

टोबी डेको ने बताया कि सिंडिकेट का सरगना नाइजीरिया में रहता है और उसे दिल्ली में रहने वाली अफ्रीकी महिला के जरिए डिलीवरी मिलती है। टोबी डेको की निशानदेही पर दिल्ली के छतरपुर इलाके में उसके किराए के कमरे से 865 ग्राम मेथामफेटामाइन बरामद किया गया। इसके बाद बेंगलुरू से फातिमा उर्फ नेहा और मोहम्मद ज़हीद उर्फ फिरोज को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद पुलिस ने ग्रेनो के सेक्टर-1 से चिकवाडो नाके किंग्सले को गिरफ्तार कर लिया।

डेड ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते थे आरोपी आरोपियों से पूछताछ में पता लगा कि वह डेड ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते थे। ये ड्रग्स को झाड़ियों या सड़क किनारे किसी सुनसान जगह पर गिरा देते थे। पकड़े जाने से बचने के लिए प्राप्तकर्ता के साथ तस्वीर और स्थान साझा किया जाता था। कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए गैर-व्यावसायिक मात्रा (50 ग्राम से कम) में बेचते थे। 2024 में उसके सिंडिकेट के कई तस्करों को केरल पुलिस ने 3 अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार किया था। आरोपी टोबी डेको ने खुलासा किया कि वह 2018 में छात्र के रूप में भारत आया था और बेंगलुरु में ड्रग्स बेचने लगा था।

जेलेंस्की तैयार हैं तो मॉस्को आ सकते हैं पुतिन ने जताई संघर्षविराम पर वार्ता की संभावना

बीजिंग, एजेंसी। रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर जारी गतिरोध के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संकेत दिया है कि वह यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलने को तैयार हैं। पुतिन ने कहा कि यदि बैठक अच्छी तरह तैयार की जाए और उससे सकारात्मक परिणाम निकलें, तो जेलेंस्की मॉस्को आ सकते हैं। इस बयान ने युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान की संभावनाओं को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

चीन दौरे से लौटने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए पुतिन ने कहा कि उन्होंने कभी भी जेलेंस्की से मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह बैठक तभी होनी चाहिए जब यह यूक्रेन के संविधान के दायरे में और सकारात्मक परिणाम देने वाली हो। पुतिन ने यह भी बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे इस बारे में सवाल किया था

और उन्होंने इसे संभव बताया।

रूस की सुरक्षा चिंताएं और नाटो पर आपत्ति

पुतिन ने दोहराया कि हर देश को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार है, लेकिन किसी भी देश की सुरक्षा दूसरे देश की कीमत पर नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की नाटो सदस्यता रूस के लिए सीधी सुरक्षा चुनौती है। हालांकि, पुतिन ने यह स्पष्ट किया कि यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल होने पर रूस की उतनी कड़ी आपत्ति नहीं है, क्योंकि यह उसकी आर्थिक गतिविधियों का हिस्सा है।

यूक्रेन का जवाब और सात देशों की पेशकश पुतिन के बयान के तुरंत बाद यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कम से कम सात देशों ने रूस-यूक्रेन वार्ता की मेजबानी की पेशकश की है, जिनमें ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, वेटिकन, तुर्किये और खाड़ी देशों के तीन राष्ट्र शामिल हैं। सिबिहा ने पुतिन के प्रस्ताव को जानबूझकर अस्वीकार्य बताया और कहा कि रूस वास्तविक शांति प्रक्रिया से बच रहा है।

बहुध्रुवीय दुनिया की वकालत पुतिन ने अपने बयान में एक और अहम बात कही। उन्होंने कहा कि अब एकध्रुवीय दुनिया का अंत होना चाहिए और सभी देशों को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। पुतिन ने साफ कहा कि किसी एक देश को विश्व राजनीति और सुरक्षा पर हावी नहीं होना चाहिए। उन्होंने ब्रिक्स और एससीओ जैसे संगठनों को बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का प्रतीक बताया।

भारत-चीन की अहमियत और पश्चिम पर निशाना पुतिन ने कहा कि आज की दुनिया में भारत और चीन जैसे आर्थिक दिग्गजों की भूमिका अहम है।

भारत के नए इमिग्रेशन नियमों से नेपाल और भूटान के नागरिकों को छूट

काठमांडू, एजेंसी। भारत सरकार ने 2 सितंबर से पूरे देश में जो नए आप्रवासन नियम लागू किए हैं उससे नेपाल और भूटान के नागरिकों को छूट दी गई है। नए नियम में किसी भी विदेशी नागरिक को भारत प्रवेश करने पर अनिवार्य रूप से फॉर्म सी भरने का निर्देश जारी किया गया है।

भारत के गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि नए आप्रवासन नियमों से नेपाल और भूटान के नागरिकों को अलग रखा गया है। गृह मंत्रालय के इस नए नियम को लेकर नेपाल में संशय उत्पन्न होने के बाद काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने एक बयान जारी कर नेपाल और भूटान के नागरिकों को इस नए नियम से अलग रखने की जानकारी दी गई है। भारतीय दूतावास ने साफ किया है कि भारत के गृह मंत्रालय के तरफ से 2 सितंबर से लागू नए आप्रवासन नियमों से नेपाल और भूटान के नागरिकों को अलग रखा गया है। इस बयान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत के गृह मंत्रालय द्वारा जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक नेपाल और भूटान के नागरिकों को नेपाल में प्रवेश करते समय पासपोर्ट या वीजा की कोई अनिवार्यता नहीं है।

नेपाल या भूटान के नागरिक अपने साथ गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित किसी भी परिचय पत्र के साथ भारत की यात्रा कर सकते हैं। इनमें पासपोर्ट या नागरिकता का प्रमाणपत्र या वोटर आईडी कार्ड में से कोई भी एक होने पर हवाई मार्ग या सड़क मार्ग से भारत में प्रवेश कर सकते हैं।

एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था अन्यायपूर्ण, बदल रहा अब शक्ति संतुलन.., पुतिन का अमेरिका पर हमला

बीजिंग,एजेंसी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था के खात्मे की पैरवी की और एक ऐसी बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था की जरूरत पर जोर दिया, जहां सभी देश बराबरी के आधार पर काम करें और कोई भी अपनी श्रेष्ठता न थोपे, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो या सुरक्षा के। चीन के चार दिवसीय दौरे के बाद पुतिन ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बराबरी की जरूरत है और ब्रिक्स व शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) जैसे संगठन इस विचार के समर्थन में हैं।

खत्म हो एकध्रुवीय व्यवस्था, नहीं होना चाहिए श्रेष्ठता थोपने वाला देश पुतिन ने कहा, एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था अन्यायपूर्ण है, यह स्पष्ट है और हम अपने संबंधों का विकास किसी बहुमत की राय के आधार पर नहीं, बल्कि एक विचार के आधार पर कर रहे हैं और वह विचार यह है कि दुनिया बहुध्रुवीय होनी चाहिए। यानी सभी अंतरराष्ट्रीय संबंधों और संवाद में शामिल पक्ष बराबर होने चाहिए। एकध्रुवीय दुनिया अब खत्म होनी चाहिए।उन्होंने आगे कहा, जहां तक यह सवाल है कि बहुध्रुवीय दुनिया बनी है या नहीं, तो इसके संकेत अब दिख रहे हैं। लेकिन मैं यह नहीं कहूं कि यह बात पूरी तरह स्थापित हो चुकी है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि इस नई बहुध्रुवीय दुनिया में कोई श्रेष्ठता (हेजमन) थोपने वाला देश होना चाहिए। ब्रिक्स में भी ऐसा

कोई नहीं कहता, एससीओ में भी नहीं।

बदल रहा वैश्विक शक्ति संतुलन, किसी को दबदबे का अधिकार नहीं पुतिन ने भारत और चीन जैसे आर्थिक ताकत वाले देशों का उदाहरण देते हुए माना कि वैश्विक शक्ति संतुलन अब बदल रहा है। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि आर्थिक ताकत का मतलब यह नहीं है कि किसी को राजनीति या वैश्विक सुरक्षा में दबदबे का अधिकार मिल जाना चाहिए।

भारत और चीन जैसे देश आर्थिक रूप से मजबूत- व्लादिमीर पुतिन उन्होंने कहा, इस बहुध्रुवीय दुनिया में सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार भी सभी बराबर होने चाहिए। हां, भारत और चीन जैसे देश आर्थिक रूप से बहुत मजबूत देश हैं। हमारी अर्थव्यवस्था भी क्रयशक्ति क्षमता के आधार पर दुनिया के शीर्ष चार में शामिल है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह अंतरराष्ट्रीय संगठनों की गणना है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी को विश्व राजनीति या सुरक्षा पर राज करना चाहिए। हम नहीं मानते कि किसी को ऐसा प्रभुत्व मिलना चाहिए। सभी बराबर हों, यही सही है।

अमेरिकी टैरिफ और पश्चिम प्रतिबंधों के बीच पुतिन का बयान पुतिन का यह बयान पश्चिमी देशों की ओर से रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों और अमेरिका की टैरिफ नीति की आलोचना के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ से कई देशों का अमेरिका के साथ तनाव बढ़ गया है, खासकर भारत और चीन के साथ। भारत इस समय वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर पचास फीसदी टैरिफ लगा दिया है, जिसमें 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ रूस से कच्चा तेल खरीदने पर लगाया गया है।

आदि कर्मयोगी अभियान के तहत तीन दिवसीय खंड स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स के जिला स्तरीय प्रोसेस लैब का शुभारंभ

सेवा, संकल्प और समर्पण की भावना के कर्मयोग से बदलेगा जनजातीय जीवन: उपायुक्त जेपी यादव

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे ष्आदि कर्मयोगी रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस प्रोग्राम के तीन दिवसीय खंड स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स के जिला स्तरीय प्रोसेस लैब का शुभारंभ होटल त्रिवेणी के सभा कक्ष में संभागीय उपायुक्त जनजाति कार्य रीवा तथा स्टेट मास्टर ट्रेनर जेपी यादव द्वारा भगवान बिरसा मुंडा के चित्र का माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलित कर किया गया। यह प्रशिक्षण जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर अतिरिक्त मुख्य मुख्य कार्यपालन अधिकारी धनंजय मिश्रा के नेतृत्व में दिया जा रहा है।

शुभारंभ अवसर पर संभागीय उपायुक्त जेपी यादव कहा कि जनजाति व्यक्ति और गांव अभी भी मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं। अंतिम छोर पर बैठे जनजाति व्यक्ति को शासन की सभी सुविधाओं का लाभ मिल सके तथा आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक, स्वास्थ्य रूप से संपन्न और आत्मनिर्भर हो सके इस हेतु कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी विभागों को मिलकर एक साथ देना होगा अभी तक के प्रयास समन्वित नहीं रहे, समन्वित और एक साथ प्रयासों से ही यह हो पाएगा। पूरे मध्य प्रदेश में इस हेतु 3 लाख शासकीय कर्मचारी और अधिकारियों को प्रतिबद्ध लीडर के रूप में तैयार किया जा रहा है। ये सभी विभिन्न विभागों से होंगे तथा मिलकर काम करेंगे। इस कार्य में समुदाय तथा सामाजिक संगठन को साथ लिया जा रहा हैं। जनजाति गांव की योजना ग्राम स्तर पर बनेगी, जिससे गांव के लोग अपनी क्या जरूरत है, उन्हें सम्मिलित कर सकेंगे। अगले 5 साल यानी 2030 तक के लिए जनजाति ग्रामों का विजन प्लान तैयार होगा। भारत सरकार, राज्य स्तर, जिला स्तर, विकासखंड स्तर पर रेस्पॉन्सिव ग्रुप का गठन किया जा रहा है। ये ग्रुप अभियान का संचालन करेंगे तथा मॉनिटरिंग करेंगे। गांव में आदि सेवा केंद्र की स्थापना की जा रही है, जिसमें विभिन्न भागों की योजनाओं की जानकारी रहेगी। ग्रामीण जन अपनी समस्याएं भी इस सेवा केंद्र पर प्रस्तुत कर सकेंगे, जिसका निराकरण समय सीमा में किया जाएगा। ब्लॉक स्तर के मास्टर ट्रेनर्स सेक्टर पर ट्रेनिंग विभिन्न विभागों के कार्यों को अभियान के मैदानी कार्य के लिए प्रशिक्षित करेंगे। ग्राम स्तर पर गतिविधियां 30 सितंबर के पूर्व संपन्न होंगी, 2 अक्टूबर को इस हेतु विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन होगा।

जीएसटी के सुधार से उपभोक्ताओं को राहत, छोटे व्यापारियों को ताक़त और भारत की अर्थव्यवस्था को गति

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। व्यापारी महासंघ ने जीएसटी सुधारों और कर दरों के पुनर्गठन को ऐतिहासिक और क्रांतिकारी करार दिया है। महासंघ के अनुसार, इन सुधारों से छोटे व्यापारियों, उपभोक्ताओं और भारत की अर्थव्यवस्था को न केवल लाभ मिलेगा बल्कि यह कदम कर संरचना को सरल बनाएगा तथा उपभोग में भारी वृद्धि कर देश की आर्थिक गतिविधियों तथा व्यापार को नई गति देगा।

महासंघ के प्रभारी संजीव गुप्ता और गुलाब साहनी ने साझा वक्तव्य जारी करके कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश भर के व्यापारियों की ओर से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 400 से अधिक वस्तुओं पर कर कम करने के सुधारों से आम आदमी को रोजमर्रा के खर्चे में बड़ी राहत मिलेगी तथा कर व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त होगी।यह वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ़ से देश को बड़ा दिवाली उपहार है ।

महासंघ के प्रवक्ता और महामंत्री ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, इन जीएसटी सुधारों से घरेलू खपत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। रिपोर्ट का अनुमान है कि आगामी त्योहारी सीजन में खपत में 7-8% की बढ़ोतरी होगी। यह उपभोक्ता खर्च में वृद्धि खुदरा व्यापार और छोटे दुकानदारों की बिक्री को सीधे लाभान्वित करेगी।

खाद व्यवस्था के संबंध में संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं के साथ जिला प्रशासन की बैठक

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। लगातार खाद संकट से जूझ रहे किसानो को राहत देने जिला प्रशासन ने चर्चा के लिए आमंत्रित कर सयुंक्त किसान मोर्चे से सुझाव मागे प्रशासन ने सपष्ट किया कि आपके सुझावो मे तत्काल अमल करेगे । सयुंक्त किसान मोर्चे के साथियो ने एक स्वर से कहा कि खाद की जगह किसानो को लाठी न दी जाय लाठी देने वालो के खिलाफ कार्रवाई कि जाय ।खाद के सकट के लिए रीवा जिले एव मऊगज जिले के साथ रीवा सभाग के सभी जिलो मे पहले सेवा सहकारी समितियो को खाद उपलब्ध करा दी जाती वहा जो किसान सदस्य है उन्हे ऋण मे एव जो किसान सदस्य नही है सेवा सहकारी समितियो से नगद मे खाद उपलब्ध करा दी जाती तो किसानो कि इतनी आफत नही होती खाद संकट सभी सेवा सहकारी समितियो मे खाद उपलब्ध न होने के कारण हुआ है जिसके लिए प्रशासन कृषि विभाग विपणन जिम्मेदार है अब भविष्य मे सभी सेवा सहकारी समितियो को पर्याप्त खाद उपलब्ध करायी जाय समितियो से किसानो को नगद ऋण दोनो मे खाद दी जाय पर्याप्त खाद मगायी जाय ।

कोयला ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर,14 साल के बेटे की मौत, पिता घायल; ग्रामीणों ने सड़क पर लगाया जाम

मीडिया ऑडीटर, सिंगरौली (निप्र)। जिले के बरगवां सड़क मार्ग पर सोमवार सुबह 7 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। कोयले से भरे एक ट्रेलर ने बाइक सवार पिता-पुत्र को टक्कर मार दी। हादसे में 14 वर्षीय आर्यन शाह की मौके पर ही मौत हो गई। उनके पिता राजेश कुमार शाह घायल हो गए।

घायल राजेश को बैढ़न के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। सीधी-सिंगरौली सड़क मार्ग ढाई घंटे से बंद है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है।

बरगवां थाना प्रभारी मोहम्मद समीर ने बताया कि पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। 50 से अधिक ग्रामीण कार्यवाही की

मांग को लेकर सड़क पर डटे हैं। दुर्घटना उस समय हुई जब पिता-पुत्र बाइक से बरगवां जा रहे थे।

हादसे के बाद कोयला लदा ट्रेलर मौके से फरार हो गया। पुलिस वाहन की तलाश कर रही है। प्रशासन ग्रामीणों और परिजनों को समझा कर जाम खुलवाने का प्रयास कर रहा है। बैढ़न से बरगवां और सीधी जाने वाले वाहनों को डायवर्ट किया गया है। पुलिस दुर्घटना की परिस्थितियों की जांच कर रही है। मौके पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।

जवा में ईद मिलाद-उन-नबी में निकाली जाएगी रैली

रीवा। ईद मिलाद-उन-नबी बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ बनाएं जाने हेतु स्थानीय पुलिस प्रशासन को कमेटी के सदस्यों ने ज्ञापन सौंपते हुए अनुमति मांगी गई है, बताया गया है कि ईद मिलाद-उन-नबी पर नगवां मस्जिद से रैली निकाली जाएगी और सितलहा होते हुए जवा चौराहे होते हुए जवा मस्जिद तक डीजे के साथ बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ रैली निकाली जाएगी। कमेटी के सदस्यों ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शान्ति सोहार्द भाईचारे के साथ ईद मिलाद-उन-नबी बनाने की परंपरा रही है। इसलिए दो बजे सर्वप्रथम मस्जिदों में नमाज अदा कर नगवां से रैली निकाली जाएगी जो सितलहा होते हुए जवा मस्जिद में समापन किया जायेगा।

देवतालाब विधानसभा क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं को लेकर कुंजबिहारी तिवारी ने मुख्यमंत्री से की मांग

मीडिया ऑडीटर, मऊगंज (निप्र)। जिला अंतर्गत देवतालाब विधानसभा की ज्वलंत समस्याओं को लेकर समाजसेवी व अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंजबिहारी तिवारी ने खुला पत्र भेज कर समस्याओं को सुनने एवं निराकरण करने की मांग की है जिनमे प्रमुख रूप से थाना प्रभारी उपनिरीक्षक जगदीश सिंह ठाकुर के द्वारा फर्जी मुकदमे दर्ज कर आम जनता, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को डराया-धमकाया जा रहा है। गांव-गांव गली-गली खुलेआम नशे का कारोबार चल रहा है जिसमें शराब, गांजा, अफीम और अन्य मादक पदार्थ आसानी से बिक रहे हैं उस पर रोक लगवाई जाय। किसान खाद के लिए दर-दर भटक रहे हैं ऊपर से बिजली बिल की मार झेल रहे हैं। निर्माण कार्यों और विकास योजनाओं में व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है।

राजनैतिक संरक्षण प्राप्त गुंडों और अराजक तत्वों द्वारा भय और आतंक का वातावरण बनाया जा रहा है। पंचायतों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अधिकार छीने जा रहे हैं। जल जीवन मिशन घोटाले में जनता को एक बूंद पानी नहीं मिला, केवल फर्जी सील और हस्ताक्षरों से कागजों पर पूर्णता प्रमाण पत्र बना दिए गए। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह बदहाल है।

संत गाडसे बाबा समिति महासंघ द्वारा गाडसे को भारतरत्न देने हेतु की गई बैठक

रीवा। संत गाडगे बाबा समिति महासंघ मध्य प्रदेश द्वारा जिला रीवा में बैठक की गई। आयोजित बैठक में यह सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित किया गया कि महान समाज सुधारक संत गाडगे महाराज को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। जिसे लेकर ओबीसी महासंघ के जिला अध्यक्ष छोटेलाल रजक ने कहा कि संत गाडगे महाराज ने अपना संपूर्ण जीवन समाज के दलित वंचित गरीब एवं शोषित वर्ग के उत्थान हेतु समर्पित थे वो स्वच्छता अभियान के प्रणेता, अंधविश्वास एवं कुरीतियों के कट्टर विरोधी तथा शिक्षा और समानता के प्रबल पक्षधर थे।

मेडिकल कॉलेज की टूटी सड़क पर लगातार हो रहे हादसे, पिता का इलाज कराने आया बेटा घायल; एमबीबीएस छात्र भी दुर्घटनाग्रस्त

मीडिया ऑडीटर, शहडोल (निप्र)। मेडिकल कॉलेज तक जाने वाली सड़क की स्थिति खराब होने से मरीजों और उनके परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे होने से दुर्घटनाएं हो रही हैं।

गड्ढे में फंसा बाइक का पहिया: ताजा मामले में संदीप प्रजापति अपने बुखार से पीड़ित पिता को मोटरसाइकिल पर लेकर मेडिकल कॉलेज जा रहे थे। मेडिकल कॉलेज से पहले ही एक बड़े गड्ढे में बाइक का पहिया फंस गया। हादसे में पिता तो बच गए, लेकिन संदीप के सर में चोट लग गई। स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया।

खराब सड़क की चपेट में एमबीबीएस छात्र भी घायल: हाईवे से करीब एक किलोमीटर दूर स्थित मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने का यही एकमात्र रास्ता है। इसी सड़क पर बुधवार रात एक एमबीबीएस छात्र भी दुर्घटनाग्रस्त होकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे भी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।

मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉ. नागेंद्र सिंह ने बताया कि इस मार्ग पर रोजाना दुर्घटनाएं हो रही हैं। रात में अंधेरे के कारण स्थिति और भी खराब हो जाती है। वे सड़क की मरम्मत के लिए संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे।

नौ सूत्रीय मांगों को लेकर ब्लाक कांग्रेस कमेटी जवा और डभौरा ने सौंपा ज्ञापन

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। जिले में व्याप्त खाद संकट को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा के निर्देशन में ब्लाक कांग्रेस जवा और डभौरा ने संयुक्त रूप महामहिम राज्यपाल ने नाम संबोधित नौ सूत्रीय मांगों का ज्ञापन तहसीलदार जवा को सौंपा गया। कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन सौंपने से पूर्व तहसील कार्यालय में जमकर नारेबाजी करते हुए शासन प्रशासन की व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाएं और कहा कि आज किसान यूरिया डीएपी खाद के लिए परेशान हैं उसे खाद नहीं मिल रही है। मिलावटी खाद एवं कालाबाजारी अपने चरम पर है। किसानों की हितैषी बताने वाली सरकार के प्रतिनिधियों के मुंह में ताले लगे हुए है।

शासन व्यवस्था बनाने में पूरी तरह फेल साबित हो रही है किसानों की खेती, आवारा मवेशियों, अघोषित बिजली कटौती एवं भारी भरकम बिजली के बिलों की बलि चढ़ी रही है जो भाजपा सरकार के दावे की पोल खोल रहा है। ज्ञापन में क्षेत्र अवैध नशे और अवैध खनन सहित शासकीय कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार, जले ट्रांसफार्मर बदले जाने सहित अन्य जनहित के मुद्दे शामिल किए गए हैं। जिसे लेकर जवा तहसीलदार जितेन्द्र तिवारी को ज्ञापन सौंपा गया गया। इस दौरान एसडीओपी डभौरा पुलिस बल के साथ मौजूद रहे।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि 16 सितंबर तक अगर प्रशासन खाद का संकट दूर नहीं कर पाती और अवैध नशीले सिरप, शराब पैकारी सहित अवैध बालू निकासी के खिलाफ कठोर कार्यवाही कर रोक नहीं लगाया गया।

गुढ पुलिस ने विस्फोटक पदार्थ के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। जिला अंतर्गत गुढ़ थाना प्रभारी शैल सिंह यादव एवं थाना पुलिस स्टॉप के सहयोग से मुखबिर की सूचना पर ग्राम इटार पहाड़ से आरोपी सौरभ प्रजापति पिता पूरन प्रजापति उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम टिकुला थाना मोहना जिला ग्वालियर हाल पता जय माँ विंध्यवासिनी इन्टर प्राइजेज मैंगजीन ग्राम लतीफपुर थाना कोरांव जिला प्रयागराज उ.प्र के कब्जे से वाहन क्र. यूपी70-एचटी-4843 मे लोड बिस्फोटक इण्डोसुपर पावर 90-32 मीमी की राड के 17 नग खाखी रंग के कार्टून जिनका वजन 25 किलोग्राम प्रति कार्टून कुल वजन 425 किलो एवं एक कार्टून खुला हुआ जिसमे करीबन 10 किलो उपरोक्त विस्फोटक राड है तथा दो बण्डल लाल रंग का ब्लास्टिंग मे उपयोग करने वाले तार व एक खुले हुये कार्टून मे विस्फोटक ऐसेसिरीज, वाहन क्र.पी70-एचटी-4843 एवं चालक द्वारा पेश संदिग्ध दस्ताबेज मुताविक जप्ती पत्रक को जप्त कर कब्जे में लिया गया। जिसके विरूद्ध गुढ़ थाने में धारा 288 बीएनएस, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 5(ए),6 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। इसके बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस के मुताबिक 2 सितम्बर को शाम करीबन 6 बजे मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक विस्फोटक वाहन जिसका नं. यूपी70-एचटी-4843 है जिसमे विस्फोटक पदार्थ भरा हुआ है।

जिले में व्यवस्थित खाद का वितरण सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। अपर जिला दण्डाधिकारी द्वारा आदेश जारी कर जिले में व्यवस्थित खाद का वितरण सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है।उन्होंने बताया कि 3 सितम्बर को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा खाद वितरण में आ रही समस्याओं के संबंध में चर्चा की गई एवं निर्देश दिये गए। इसी क्रम में कमिश्नर रीवा संभाग रीवा (म.प्र.) द्वारा सायं काल वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से खाद वितरण में आ रही समस्याओं के संबंध में चर्चा की गई तथा निर्देशित किया गया कि आगामी 4 दिनों तक जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता खाद का सफल एवं शांतिपूर्ण तरीके से वितरण कराना रहेगा। उक्त निर्देश के पालन के लिए अधिकारियों की ड्यूटी कार्य दायित्व हेतु लगाई गई है।

जारी आदेशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला सीधी डबल लॉक एवं वितरण केन्द्रो में पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था करेंगे। समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला सीधी वितरण केन्द्रो पर 01 तहसीलदार के साथ पटवारी एवं कोटवारों की ड्यूटी लगाना सुनिश्चित करेंगें। समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जिला सीधी डबल लॉक पर रोटेशन अनुसार हर रोज़ 5-5 सचिव/ग्राम रोजगार सहायक की ड्यूटी उस सेक्टर के उपंयत्री के साथ लगाना सुनिश्चित करेंगें।

डायल 100 की जगह अब डायल 112, 19 अत्याधुनिक वाहनों से मिलेगी पुलिस; एंबुलेंस और फायर की सेवाएं

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। जिले में नागरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा शुरू की गई है। पुलिस अधीक्षक डॉ. रवींद्र वर्मा ने गुरुवार को पुलिस लाइन परिसर से 19 नए एफआरवी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन जिले के विभिन्न थाना और चौकियों में तैनात किए जाएंगे।

पुलिस मुख्यालय द्वारा विशेष रूप से आवंटित किए गए ये वाहन तीन सेवाएं एक साथ देंगे - पुलिस सहायता, एंबुलेंस सेवा और अग्निशमन सेवा। इन वाहनों में आधुनिक तकनीक और उपकरण लगे हैं। जीपीएस सिस्टम और लाइव कैमरा घटनास्थल की रियल-टाइम लोकेशन और मॉनिटरिंग करेंगे।

बॉडी वार्न कैमरा पुलिस कार्रवाई में पारदर्शिता लाएगा। डैश कैमरा घटनास्थल का सटीक रिकॉर्ड रखेगा।

वाहनों में फर्स्ट एड किट और स्ट्रेचर से तत्काल प्राथमिक उपचार की सुविधा मिलेगी। अग्निशमन यंत्र आपातकालीन स्थितियों में राहत पहुंचाएगा। एसपी डॉ. वर्मा ने कहा कि इन वाहनों से जिलेवासियों को तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद आपातकालीन सहायता मिलेगी। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव, डीएसपी अमन मिश्रा, रक्षित निरीक्षक वीरेंद्र कुमरे, निरीक्षक देवेंद्र सिंह और वाहन शाखा प्रभारी उपनिरीक्षक रामनरेश साकेत सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे।

घुटनों का दर्द, हर उम्र में बढ़ती परेशानी : डॉ. राजीव अग्निहोत्री

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। आजकल घुटनों का दर्द केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रहा बल्कि कम उम्र में भी जीवनशैली, खानपान और कामकाजी दबाव के कारण यह समस्या बढ़ रही है। जिसे लेकर आयुर्वेद शासकीय महाविद्यालय रीवा के सुप्रसिद्ध आयुर्वेद डॉ. राजीव अग्निहोत्री ने बताया कि घुटने का दर्द मुख्य रूप से वात दोष की वृद्धि से होता है। इसे समय रहते समझना और उपचार करना आवश्यक है।

घुटने के दर्द के मुख्य कारण: बढ़ती उम्र और हड्डियों का घिसना (ऑस्टियोआर्थराइटिस), मोटापा और वजन का दबाव, चोट या मोच, लंबे समय तक

खड़े रहना या भारी काम करना, असंतुलित खानपान (अत्यधिक तैलीय, ठंडी, गैस बनाने वाली चीजें) मुख्य कारण है। उन्होंने बताया कि वात दोष के दौरान घुटनों में अकड़न और सूजन, सीढ़ियाँ चढ़ते-उतरते दर्द, सुबह उठने पर जकड़न, चलने में खटखटाहट (क्रेकिंग साउंड), बैठने और खड़े होने में तकलीफ़ होने जैसे लक्षण दिखाई व महसूस होने लगेंगे।

विरोध कहां तक

संपादकीय

मुंबई में मराठा आरक्षण को लेकर पांच दिनों तक प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगें मनवाई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आंदोलन के दौरान संपत्ति के नुकसान पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने आम लोगों को हुई असुविधा पर नाराजगी जताई।

देश ने आरक्षण की एक और लड़ाई देखी, इस बार मुंबई में। मराठा आरक्षण को लेकर पांच दिनों तक भारत की आर्थिक राजधानी में हंगामा मचा रहा। प्रदर्शनकारी आखिरकार माने, लेकिन अपनी कई मांगें मनवा कर। प्रदर्शन खत्म हो चुका है, पर इससे जुड़े कुछ सवाल अब भी बाकी हैं - अपनी मांग को लेकर कोई आंदोलन किस हद तक जा सकता है और क्या विरोध-प्रदर्शन का अधिकार छीना जा सकता है?

अदालत की सख्ती- बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल से जवाब मांगा है कि आंदोलन के दौरान सरकारी संपत्ति को जो बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा, उसका जिम्मेदार कौन है? जरांगे की तरफ से बताया गया कि आंदोलन शांतिपूर्ण था, किसी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि यह माना गया कि आम जनता को असुविधा हुई। गौरतलब है कि यह आंदोलन खत्म भी तभी हुआ, जब हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई - भले इसके लिए सरकार ने जरांगे की मांगें मानीं।

आंदोलन से परेशानी- आम लोगों को हुई असुविधा पर हाई कोर्ट की नाराजगी बिल्कुल सही है। अपनी बात मनवाने के लिए किसी शहर की रफ्तार को रोक देना उचित नहीं माना जा सकता। दुर्भाग्य से दक्षिण मुंबई को जबरदस्त परेशानी झेलनी पड़ी - कई लोकल ट्रेन कैंसल हुईं और कभी न थमने वाली मुंबई का कुछ हिस्सा आरक्षण आंदोलन में जकड़ गया।

प्रशासन की जिम्मेदारी- लेकिन यहां जितनी जिम्मेदारी आंदोलनकारियों, उनके नेता जरांगे की है, उतनी ही एडमिनिस्ट्रेशन की भी। मुंबई में भीड़ का उमड़ना कोई नई बात नहीं है। गणेश पूजनोत्सव के दौरान ही देश के तमाम हिस्सों से लोग गणपति बप्पा के दर्शन को मुंबई पहुंचते हैं। तो क्या आंदोलन की जानकारी होने के बाद हालात को संभालने के लिए उचित इंतजाम किए गए थे? अगर परमिशन पांच हजार की थी, तो इससे कई गुना ज्यादा भीड़ कैसे महानगर में दाखिल हो गई? संतुलन जरूरी- विरोध-प्रदर्शन लोकतंत्र का अहम हिस्सा है। सरकार से असहमति जताना और जिम्मेदारों तक अपनी बात पहुंचाना हर नागरिक का हक है। अगर किसी समुदाय-वर्ग को लगता है कि सरकार उसके हितों की अनदेखी कर रही है, तो उसे विरोध जताने से नहीं रोका जा सकता। लेकिन, मामला है हद का - कि उस विरोध की सीमा क्या होगी? जिस तरह विरोध का अधिकार नहीं छीना जा सकता, उसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि एक का प्रदर्शन दूसरे के लिए आफत बन जाए। महाराष्ट्र सरकार ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। जरूरत है कि इस सवाल को भी सुलझा लिया जाए, वरना फिर कोई शहर किसी आंदोलन के बोझ से दबा होगा।

राष्ट्रीय चिंता का विषय बने घुसपैठिए, विकास को बाधित करने के अलावा लोकतंत्र के लिए भी खतरा

अशोक कुमार।

घुसपैठ एक क्षेत्रीय चुनौती ही नहीं बल्कि भारत की राजनीतिक इच्छाशक्ति नीतिगत संकल्प और सामाजिक एकता की एक बुनियादी परीक्षा भी है। इसके लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय प्रतिक्रिया आवश्यक है जो अल्पकालिक राजनीति से ऊपर उठे। यदि यह मुद्दा अनसुलझा रहा तो अस्थिरता की आशंका बढ़ेगी। घुसपैठिए देश की आंतरिक शांति को खतरे में डालने के साथ ही विकास को बाधित कर सकते हैं।

सीमा पार से घुसपैठ भारत की सबसे गंभीर आंतरिक सुरक्षा चिंताओं में से एक बन गई है। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इस खतरे को रेखांकित करते हुए कहा, 'अवैध घुसपैठिए हमारे युवाओं की रोजी-रोटी छीन रहे हैं, हमारी बेटियों और बहनों को निशाना बना रहे हैं और निर्दोष आदिवासियों की वन भूमि पर कब्जा कर रहे हैं।' उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में इन जनसांख्यिकीय बदलावों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया।

इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने एक उच्चस्तरीय जनसांख्यिकीय सुरक्षा मिशन के गठन की घोषणा भी की है। यह इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए एक दृढ़ प्रयास का संकेत देता है। घुसपैठ अब केवल सीमा-विशेष के स्तर पर ही समस्या नहीं रह गई है। दिल्ली, हैदराबाद, गुरुग्राम और पुणे जैसे प्रमुख शहरों में घुसपैठियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इससे शहरी सेवाओं और व्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है। इसके दूरगामी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिणाम भी सामने आ रहे हैं।

घुसपैठ एक राष्ट्रीय चिंता बन गई है। बांग्लादेश और म्यांमार से आए घुसपैठियों ने असम, बंगाल, त्रिपुरा और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की जनसांख्यिकीय संरचना को बदल दिया है। इससे सामाजिक संतुलन बिगड़ा है। इसके चलते भूमि, भाषा और पहचान को लेकर टकराव पैदा हो रहा है। स्थानीय लोगों में धारणा बढ़ रही है कि घुसपैठिए कल्याणकारी योजनाओं और राजनीतिक तुष्टीकरण का लाभ उठा रहे हैं।

इस धारणा ने जातीय राष्ट्रवाद और सांप्रदायिक तनाव को जन्म दिया है। कट्टरपंथी समूह ऐसी भावनाओं का फायदा उठाने में तत्पर रहते हैं, जिससे सामाजिक एकता को और खतरा पैदा होता है। इस समस्या को विकराल बनाने में राजनीतिक दल भी कम दोषी नहीं। अधिकांश दलों ने वोट-बैंक के लिए जाली दस्तावेजों के जरिये घुसपैठियों को सरकारी जमीनों खासकर नदियों के निकट और वन क्षेत्रों में बसाने में मदद की है।

अल्पकालिक चुनावी लाभ के लिए इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ दीर्घकालिक समझौता हो जाता है। इससे नागरिकों और राज्य के बीच अविश्वास गहराता है। समय रहते अगर इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह भारी अशांति का कारण बन सकता है, विशेषकर उन संवेदनशील क्षेत्रों में जहां जनसांख्यिकीय दबाव बढ़ रहा है। इसके तब और विध्वंसक परिणाम सामने आते हैं जब घुसपैठिए कृषि, निर्माण और घरेलू मजदूरी से जुड़े काम में संलग्न हो जाते हैं। इससे बाजार सस्ते मजदूरों से भर जाता है और स्थानीय श्रमिकों के हितों पर चोट पहुंचती है। सुरक्षा के जोखिम अलग बढ़ जाते हैं।

कई घुसपैठिए अनौपचारिक या ग्रे इकोनमी में भी लिप्त होते हैं, जहां वे पशु तस्करी, मादक पदार्थों, जाली मुद्रा और अन्य अवैध गतिविधियों में लिप्त होते हैं। ये गतिविधियां न केवल औपचारिक अर्थव्यवस्था को कमजोर करती हैं, बल्कि संगठित अपराध सिंडिकेट को भी मजबूत बनाती हैं। इनमें से कुछ के आतंकवादियों से संबंध भी होते हैं। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कल्याणकारी योजनाओं पर भी घुसपैठिए बोझ बढ़ा रहे हैं। इस बोझ के चलते 2047 तक भारत के एक विकसित राष्ट्र बनने का सपना भी पटरी से उतर सकता है। शत्रु पक्ष की रणनीतियों के कारण भारत की सीमाओं पर समस्याएं बढ़ रही हैं। पंजाब में ड्रोन के जरिये ड्रग्स और हथियार से जुड़े आतंकवाद ने जोर पकड़ लिया है। भारत-म्यांमार सीमा पर दुर्गम इलाके उग्रवादियों की आवाजाही और अवैध प्रवेश को बढ़ावा देते हैं। साइबर अपराधियों और मजदूरों के वेश में छिपे गुप्त एजेंट जांच को और जटिल बना देते हैं। बीते दिनों बांग्लादेश-मेघालय सीमा पर पाकिस्तानी आर्तकियों की गिरफ्तारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ द्वारा एक रणनीतिक बदलाव का संकेत देती है, जो अब पूर्वी सीमा पर कमजोरियों का फायदा उठाने के फेर में है। सुरक्षा बलों की भरसक कोशिशों के बावजूद व्यापक भौगोलिक परिस्थितियां भी प्रवर्तन संबंधी चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। 2011 में मालदा जिले में पशु तस्करों ने एक हेड कांस्टेबल की हत्या कर दी थी। एक सर्वेक्षण के अनुसार 500 मीटर क्षेत्र पर अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों ने कब्जा किया हुआ था।

शिक्षा का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट और अल्पसंयक संस्थाएं

डॉ. निवेदिता शर्मा

भारत का लोकतांत्रिक संविधान नागरिकों को केवल राजनीतिक अधिकार ही नहीं देता, बल्कि उन्हें गरिमामय जीवन जीने की बुनियादी गारंटी भी प्रदान करता है। शिक्षा इस गारंटी की केंद्रीय धुरी है। अनुच्छेद 21ए के तहत छह से चौदह वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान इसीलिए किया गया था ताकि कोई भी बच्चा वर्ग, धर्म या आर्थिक स्थिति के कारण ज्ञान के अवसर से वंचित न रह जाए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि शिक्षा के इस सार्वभौमिक अधिकार को सबसे मजबूत दीवार को ही वर्षों पहले एक न्यायिक निर्णय ने दरका दिया। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम भारत संघ प्रकरण में यह कह दिया गया कि अल्पसंख्यक संस्थान आरटीई अधिनियम से मुक्त रहेंगे। यानी निजी स्कूलों की तरह उन्हें 25 प्रतिशत सीटें वंचित बच्चों के लिए आरक्षित करने की बाध्यता नहीं होगी। देखा जाए तो यह फैसला अपने आप में शिक्षा के अधिकार की सार्वभौमिकता पर प्रश्नचिह्न था।

अब, ग्यारह वर्ष बाद, शीर्ष अदालत ने स्वयं यह महसूस किया है कि उस निर्णय से व्यापक अन्याय हुआ है। 1 सितंबर 2025 को न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने बेहद गंभीर टिप्पणी करते हुए इस मुद्दे को संविधान पीठ के पास भेजने की सिफारिश की है। पीठ ने साफ कहा, यह फैसला अनजाने में अनुच्छेद 21ए के मकसद को कमजोर करता है और समान स्कूल प्रणाली की अवधारणा को चोट पहुँचाता है। आज न्यायालय ने यह भी इंगित किया कि आरटीई केवल सीट आरक्षण भर नहीं है, बल्कि इसके साथ कई आवश्यक प्रावधान जुड़े हैं; बच्चों को मुफ्त यूनिफॉर्म, किताबें, मिड-डे मील, प्रशिक्षित शिक्षक और बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराना। इन सबसे अल्पसंख्यक संस्थानों को छूट देकर अब तक न जानें कितने लाख बच्चों को इन बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया गया है।

अभी 2025 तक का इस संबंध में कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, हालांकि सरकारी आँकड़ों (यूडीआईएसई+ 2021-22) के अनुसार, देश में 51,627 अल्पसंख्यक प्रबंधित स्कूल हैं। इनमें मुस्लिम संस्थान; 27,259, ईसाई संस्थान; 15,808, जैन संस्थान; 1,140, बौद्ध संस्थान; 720, पारसी संस्थान;126 और शेष में अन्य शामिल हैं। पिछले तीन साल में इस संख्या में और अधिक इजाफा हुआ है। अनुमान है कि उक्त संख्या 55 हजार तक पहुंच गई होगी। ऐसे में यह स्वभाविक है कि यह संख्या अपने आप में बहुत बड़ी है। जब इतने बड़े हिस्से को आरटीई की बाध्यता से छूट मिल जाए, तो स्पष्ट है कि लाखों वंचित बच्चों को समान शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाया ।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 23,487 अल्पसंख्यक स्कूलों का विश्लेषण किया था। यह रिपोर्ट बताती है कि इन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों में केवल 38त्न विद्यार्थी संबंधित अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, शेष 62त्न गैर-अल्पसंख्यक। महज 8.76त्न विद्यार्थी सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं। स्पष्ट है कि अधिकांश अल्पसंख्यक संस्थान अपने ही समुदाय के उत्थान के बजाय शिक्षा को व्यवसाय बना चुके हैं। यदि वे सचमुच अपने वर्ग के बच्चों को प्राथमिकता देते, तो न केवल अपने समुदाय का बड़ा भला करते, बल्कि संविधान की भावना के अनुरूप भी चलते।

यहां उदाहरण स्वरूप सबसे छोटा एक आंकड़ा मान लें कि एक औसत स्कूल में 200ङ्क300 विद्यार्थी पढ़ते हैं। यदि 25 प्रतिशत सीटें वंचित वर्ग के लिए आरक्षित होतीं, तो प्रति स्कूल लगभग 50 सीटें आरटीई के अंतर्गत आतीं। 51,627 स्कूल म 50 सीटें = लगभग 25.8 लाख सीटें प्रति वर्ष। 2010 से 2025 तक यानी 15 वर्षों में यह संख्या करीब 3.8 करोड़ अवसरों के बराबर है। इस मोटे अनुमान से ही स्पष्ट है कि कितने विशाल पैमाने पर वंचित बच्चों को शिक्षा से अब तक इन स्कूलों द्वारा अल्पसंख्यक के नाम पर वंचित रखा गया !

राजस्थान के जयपुर में ही इस साल 2025 में 30,000 बच्चों को आरटीई के तहत दाखिला नहीं मिला, जबकि 80,000 सीटों पर 3.8 लाख आवेदन आए। देश की राजधानी दिल्ली में 2023-24 में 2.09 लाख परिवारों ने 35,000 सीटों के लिए आवेदन किया, लेकिन 6,500 सीटें खाली रह गईं। अहमदाबाद में तीसरे राउंड में भी 6,946 सीटें खाली रहीं, खासकर अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में। दक्षिण कर्नाटक; 2025-26 में 326 सीटों में से केवल 31 भरी गईं। यानी अल्पसंख्यक स्कूलों को यदि ये छूट नहीं दी जाती तो जो बच्चे आरटीई के तहत प्रवेश लेने से वंचित रह गए, उनमें किसी एक को भी वंचित नहीं रहना पड़ता। वस्तुत- यह तो कुछ राज्यों की स्थि?ति है, इस तरह से प्रत्येक राज्य के आंकड़े को जोड़ा जाएगा तो लाखों बच्चों की संख्या सामने आती है जो हर साल आरटीई के तहत स्कूल प्रवेश से वंचित रह जाते हैं। यह सब दिखाता है कि समस्या केवल नाम की नहीं, बल्कि व्यावहारिक है, बच्चे अवसर से वंचित हो रहे हैं।

यह दिलचस्प तथ्य यह है कि 2009 में आरटीई लागू होने के बाद अल्पसंख्यक संस्थानों की संख्या में अचानक उछाल आया। 2012 तक हर साल लगभग 2000 नए संस्थान अल्पसंख्यक दर्जा लेने लगे। यहाँ तक कि दिल्ली पब्लिक स्कूल, बेंगलुरु जैसी संस्थाओं ने भी इस दर्जे का लाभ उठाने की कोशिश की। यह प्रवृत्ति बताती है कि आरटीई से बचने के लिए अल्पसंख्यक टैग को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया। सवाल उठता है, आखिर ये आरटीई से बचने की होड़ क्यों मची है ?

मूल प्रश्न यह है कि क्या शिक्षा का उद्देश्य वंचित बच्चों को अवसर देना है या केवल मोटा पैसा कमाना? जब अल्पसंख्यक संस्थान आरटीई से मुक्त होकर भारी फीस लेते हैं, तो वे न तो अपने वर्ग का उत्थान कर रहे होते हैं और न ही समाज के वंचित वर्ग का। वे केवल शिक्षा को व्यापार बना रहे होते हैं। यदि ये संस्थान केवल अपने समुदाय के गरीब बच्चों को प्रवेश देते, तो लाखों अल्पसंख्यक बच्चे पढ़-लिखकर आगे बढ़ सकते थे। लेकिन जब ऐसा नहीं किया गया, तो साफ है कि मकसद शिक्षा नहीं, बल्कि आर्थिक लाभ है।

जब वंचित वर्ग के लाखों बच्चे आरटीई सीटों से वंचित रहते हैं, तो इसका असर केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहता। इसका असर उनके भविष्य, रोजगार, सामाजिक गतिशीलता और लोकतांत्रिक भागीदारी पर पड़ता है। एक ओर समृद्ध वर्ग के बच्चे महंगे निजी या अल्पसंख्यक स्कूलों में पढ़ते हैं, दूसरी ओर गरीब बच्चे सरकारी स्कूलों की कमजोर व्यवस्था में सिमट जाते हैं। यह विभाजन समाज में असमानता की खाई को और चौड़ा करता है।

संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 30 के जरिए अल्पसंख्यकों को संस्थान चलाने की स्वतंत्रता दी थी ताकि वे अपनी संस्कृति और पहचान बचा सकें। लेकिन क्या इस स्वतंत्रता का मतलब यह है कि वे बच्चों के बुनियादी अधिकारों से मुकर जाएँ? वास्तव में अनुच्छेद 21ए की आत्मा सार्वभौमिकता है। यानी हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार देना है। स्वभाविक है ऐसी स्थि?ति में हमें अनुच्छेद 30 स्थान पर अनुच्छेद 21ए को ही अधिक महत्व देना होगा। क्योंकि यहां प्रश्न एवं जवाबदेही अपनी पीढ़ि?यों के निर्माण की है।

भारत ने यूनेस्को एजुकेशन फॉर ऑल और सतत विकास लक्ष्य 4 (एसडीजी-4) जैसे वैश्विक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनका लक्ष्य है, 2030 तक हर बच्चे को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करा देना है। ऐसे में फिर स्वभाविक तौर पर अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीई से छूट देना इन अंतरराष्ट्रीय वचनों के भी विपरीत है। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इस निर्णय पर पुनर्विचार के लिए तैयार है, तो समय आ गया है कि शिक्षा को फिर से अधिकार की तरह देखा जाए, न कि व्यवसाय की तरह। कुछ ठोस कदम आवश्यक हैं। यहां हम सभी समझें, यदि शिक्षा अधिकार है, तो कोई भी संस्था, चाहे वह अल्पसंख्यक क्यों न हो, वह बच्चे से उसका ये मौलिक अधिकार नहीं छीन सकती है, क्योंकि वह इस अधिकार से कभी ऊपर नहीं हो सकती।

अमेरिकी टैरिफ, मजबूत भारत, इक्विटी बाजार की आत्मनिर्भरता और नए बाजार

असल में भारतीय इक्विटी बाजार की असली ताकत अब घरेलू निवेशकों की बढ़ती भागीदारी है। पहले विदेशी संस्थागत निवेशक यानी एफआईआई भारतीय बाजार का मूड तय करते थे। उनकी भारी खरीद या बिकवाली से बाजार झूल जाता था। लेकिन बीते कुछ वर्षों में तस्वीर बदल गई है। वित्त वर्ष 2024-25 में घरेलू संस्थागत निवेशकों ने लगभग 71.6 अरब डॉलर का निवेश किया, जिसमें से करीब 55 अरब डॉलर सिर्फ म्यूचुअल फंड्स से आए।

डॉ. मयंक चतुर्वेदी

अमेरिका द्वारा भारत से निर्यातित वस्तुओं पर 50 प्रतिशत तक का टैरिफ लगाए जाने की घोषणा वैश्विक स्तर पर एक बड़ी खबर रही। आम तौर पर ऐसे कदम किसी भी उभरती अर्थव्यवस्था को गहरे स्तर पर प्रभावित कर सकते हैं। व्यापारिक रिश्तों में तनाव, कंपनियों की आय पर दबाव और विदेशी निवेशकों की सतर्कता, ये सभी ऐसे हालात में सामने आते हैं, किंतु भारतीय इक्विटी बाजार ने इस निर्णय पर जिस संतुलित और आत्मविश्वासी ढंग से प्रतिक्रिया दी है, वह आज की नई आर्थिक हकीकत को सामने लाती है।

इसे देखते हुए यही कहना होगा कि अब भारत केवल बाहरी कारकों पर निर्भर नहीं है, वह अपने भीतर ऐसी ताकतें पैदा कर चुका है जो उसे वैश्विक झटकों से बचाने में सहायक हैं। यही बदलते भारत की कहानी है, एक ऐसा भारत जो निवेशकों के भरोसे से मजबूत है और अपनी घरेलू क्षमता से टिकाऊ वृद्धि की राह पर बढ़ रहा है। वस्तुत- दो सितंबर 2025 को जारी एचएसबीसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिसर्च की रिपोर्ट में साफ कहा गया कि अमेरिकी टैरिफ का भारतीय इक्विटी बाजार पर कोई बड़ा असर नहीं होगा।

रिपोर्ट के अनुसार बीएसई-500 की सूचीबद्ध कंपनियों में से चार प्रतिशत से भी कम कंपनियाँ अमेरिकी निर्यात पर निर्भर हैं। इसका मतलब है कि व्यापक स्तर पर भारतीय कॉरपोरेट जगत की कमाई पर इन टैरिफ का सीधा प्रभाव न के बराबर है। यही नहीं, फार्मास्यूटिकल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र को इन टैरिफ से छूट दी गई है, जिससे भारत की सबसे प्रतिस्पर्धी और वैश्विक स्तर पर सबसे मान्यता प्राप्त उद्योग शाखा सुरक्षित बनी हुई है। स्पष्ट है कि इस कदम से भारतीय बाजार को झटका भले लगा हो, लेकिन उसकी जड़ें हिलाने वाली स्थिति नहीं बनी।

असल में भारतीय इक्विटी बाजार की असली ताकत अब घरेलू निवेशकों की बढ़ती भागीदारी है। पहले विदेशी संस्थागत निवेशक यानी एफआईआई भारतीय बाजार का मूड तय करते थे। उनकी भारी खरीद या बिकवाली से बाजार झूल जाता था। लेकिन बीते कुछ वर्षों में तस्वीर बदल गई है। वित्त वर्ष 2024-25 में घरेलू संस्थागत निवेशकों ने लगभग 71.6 अरब डॉलर का निवेश किया, जिसमें से करीब 55 अरब डॉलर सिर्फ म्यूचुअल फंड्स से आए।

दूसरी ओर, विदेशी निवेशकों ने इसी दौरान लगभग 15.6 अरब डॉलर की बिकवाली की। इसके बावजूद बाजार स्थिर बना रहा। जुलाई 2025 में घरेलू म्यूचुअल फंडों में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) के माध्यम से 28,464 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड निवेश हुआ। यह आँकड़ा दर्शाता है कि भारतीय बचत और निवेश की धाराएँ अब देश के पूँजी बाजार को संभालने में सक्षम हो चुकी हैं। यही कारण है कि अमेरिकी टैरिफ या विदेशी निवेशकों की बिकवाली का असर सीमित रहा।

यहां रिपोर्ट यह भी बताती है कि भारतीय बाजार के लिए नौ में से पाँच प्रमुख जोखिम कारकों में सुधार हो रहा है। इनमें मुद्रास्फीति का थमना, सरकारी कर प्रोत्साहन, उपभोग की संभावनाओं में बढ़ोत्तरी और वेतन वृद्धि की उम्मीदें शामिल हैं। मुद्रास्फीति का थमना सबसे अहम है, क्योंकि यह सीधे उपभोक्ता की क्रय शक्ति को बढ़ाता है। जब रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च कम होता है, तो उपभोक्ता अन्य वस्तुओं और सेवाओं पर अधिक खर्च कर सकता है। इससे खपत बढ़ती है और कंपनियों की बिक्री तथा मुनाफे पर सकारात्मक असर पड़ता है। हालाँकि एचएसबीसी ने यह भी चेतावनी दी है कि 2025 में आय वृद्धि घटकर 8ङ्क9 प्रतिशत रह सकती है, जबकि कैलेंडर वर्ष के लिए यह अनुमान 11 प्रतिशत का है। यह विरोधाभासी तस्वीर बताती है कि चुनौतियाँ अब भी बनी हुई हैं।

टैरिफ का असर वास्तव में कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए आँकड़ों पर नजर डालना आवश्यक है। भारत का अमेरिकी निर्यात लगभग 81 अरब डॉलर का है, जो सकल घरेलू उत्पाद का करीब 2.1 प्रतिशत है। अतिरिक्त टैरिफ का असर जीडीपी वृद्धि पर लगभग 0.3 प्रतिशत अंक तक हो सकता है। यह निश्चित रूप से अप्रिय है लेकिन किसी बड़ी तबाही जैसा नहीं। इसका सबसे अधिक दबाव टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी और समुद्री उत्पाद जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों पर होगा। ये क्षेत्र न केवल निर्यातक हैं बल्कि बड़ी संख्या में रोजगार भी प्रदान करते हैं। इसलिए वहाँ पर चिंताएँ अधिक गंभीर हैं। इसके विपरीत, फार्मा और स्मार्टफोन जैसे सेक्टर को छूट मिलने से यह स्पष्ट है कि अमेरिका की नीति पूरी तरह से व्यापक नहीं है, बल्कि सर्जिकल है, जहाँ दबाव डालना है वहाँ टैरिफ लगाया गया और जहाँ अमेरिका की अपनी सप्लाई-चेन निर्भर है, वहाँ राहत दी गई।

यदि व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह पूरी स्थिति भारत के आर्थिक लचीलेपन को दर्शाती है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की विकास दर 2025 और 2026 दोनों वर्षों के लिए 6.4 प्रतिशत आँकी है। विश्व बैंक ने भारत को ''सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था'' करार दिया है। मूडीज़ और एसएंडपी जैसी रेटिंग एजेंसियों ने भी भारत की साख को स्थिर बनाए रखा है। ये सभी टिप्पणियाँ इस बात का संकेत हैं कि वैश्विक संस्थाएँ भारत को अब एक विश्वसनीय और दीर्घकालिक निवेश गंतव्य मानती हैं। भारतीय इक्विटी बाजार की तुलना अगर चीन से की जाए तो एक दिलचस्प समानता सामने आती है। चीन का बाजार भी स्थानीय निवेशकों से संचालित है और वहाँ भी विदेशी भागीदारी सीमित है। लेकिन चीन की नीतिगत अपारदर्शिता और भू-राजनीतिक जोखिमों ने विदेशी निवेशकों को सतर्क बना दिया है। इसके विपरीत, भारत का लोकतांत्रिक ढाँचा, पारदर्शी नीतियाँ और आईटी तथा सेवाक्षेत्र की बढ़त उसे निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बनाती हैं। यही कारण है कि एचएसबीसी ने भी माना कि भारतीय और चीनी दोनों बाजार एक साथ अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन भारत की स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत है। अमेरिकी टैरिफ या किसी भी बाहरी दबाव के बीच भारत की यह मजबूती केवल आर्थिक कहानी नहीं है। यह उस आत्मनिर्भरता की ओर इशारा है जिसकी चर्चा पिछले कुछ वर्षों से लगातार होती रही है। सरकार की प्रोत्साहन योजनाएँ, डिजिटल और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ते कदम और घरेलू निवेशकों का भरोसा मिलकर भारत को एक नई आर्थिक स्थिरता दे रहे हैं। फिर भी आज की सच्चाई यही है कि भारतीय इक्विटी बाजार अब वैश्विक झटकों का केवल शिकार नहीं रहा।

वस्तुत- कहना होगा कि अमेरिकी टैरिफ इसका हालिया उदाहरण है। इस निर्णय ने भारत के बाजार को हिलाया नहीं, बल्कि उसकी लचीलापन और आत्मनिर्भरता को और उजागर किया है। निवेशकों का भरोसा, बचतों की मजबूत धारा और नीतिगत स्थिरता भारत को उस मुकाम पर पहुँचा रही है जहाँ वह वैश्विक ताकतों की चालों से डरने के बजाय अपने दम पर आगे बढ़ सकता है। इसके साथ ही इस नई चुनौती का सामना करने के लिए मोदी सरकार ने विश्व के नए 40 बाजार और खोज लिए हैं, जल्द ही यहां भारतीय माल की खपत आरंभ कर दी जाएगी, स्वभाविक है कि इससे जो रोजगार पैदा होंगे वह वर्तमान से बहुत अधिक होंगे।

जनदर्शन में सुनी आम नागरिकों की समस्याएं

जनदर्शन में मिले 77 आवेदन

गरियाबंद, एजेंसी। कलेक्टर भगवान सिंह उइके ने आज जनदर्शन में जिले के अलग-अलग क्षेत्रों से आये लोगों की मांग, समस्याएं एवं शिकायतें सुनी। कलेक्टर ने आज जनदर्शन में 77 लोगों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना और संबंधित अधिकारियों को आवेदनों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। जनदर्शन में ग्राम पाण्डुका की ममता साहू ने आर्थिक प्रकरण मे देय राशि प्रदान करने, ग्राम पाण्डुका के अजीज खान ने आवास योजना का लाभ दिलाने, ग्राम सोरिद खुर्द के बिसंभर ने प्रधानमंत्री बीमा का लाभ दिलाने, ग्राम सोरिद खुर्द की गीताबाई ने प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिलाने, ग्राम नवापारा के चन्द्रभान ने काबिज भूमि पर आवास निर्माण करने, ग्राम रावनसिंघी के चमन कुमार सिंह ने मासिक वेतन प्रदाय करने, ग्राम मुडगेलमाल के विजय बेहरा ने कामन सर्विस सेंटर खोलने, ग्राम खट्टी की कुन्तीबाई ने इलाज हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने, ग्राम जरगांव के पुनित साहू ने पट्टा प्रदान करने, ग्राम कोसमकानी के महेश ने आवास का राशि प्रदान करने, ग्राम मुडगांव के रामप्यारी ने राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करने, नगर पंचायत राजिम के पुनूराम ने सीमांकन हेतु नक्शा प्रदान करने, ग्राम सोरिदखुर्द की लताबाई ने शौचालय बनाने सहायता राशि प्रदान करने, ग्राम सोरिद खुर्द के बंसत सिन्हा ने तटबंध बनाने, ग्राम पेण्ड्रा के गिरधर ने त्रण प्रदान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किये है। इस पर कलेक्टर उइके ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये। इस अवसर पर जिला पंचायत के सीईओ प्रखर चन्द्राकर, अपर कलेक्टर प्रकाश राजपूत, नवीन भगत, पंकज डाहिरे, सभी एसडीएम, जनपद सीईओ सहित जिला अधिकारी मौजूद रहे।

लेखा प्रशिक्षण के लिए आवेदन 30 सितंबर तक

गरियाबंद, एजेंसी। संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन के आदेशानुसार शासकीय लेखा प्रशिक्षण शाला रायपुर में सत्र नवंबर 2025 से फरवरी 2026 के लिए 1 सितंबर 2025 से 30 सितंबर 2025 की अवधि में आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे। इस तिथि के पूर्व एवं पश्चात प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार नही किया जाएगा। प्राचार्य शासकीय लेखा प्रशिक्षण शाला से मिली जानकारी के अनुसार लेखा प्रशिक्षण सत्र नवंबर 2025 से फरवरी 2026 के लिए 3 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके लिपिक वर्गीय कर्मचारी अपने कार्यालय प्रमुख के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र भेज सकते है। यह आवेदन शासकीय लेखा प्रशिक्षण शाला, नगर घड़ी चौक रायपुर को 30 सितंबर 2025 तक कार्यालयीन समय में प्राप्त हो जाना चाहिए।लिपिक वर्गीय कर्मचारी से आशय ऐसे कर्मचारी से है जिनकी पदस्थापना लिपिकीय संवर्ग के पद पर हुई है न कि किसी तकनीकी संवर्गीय पद पर। मानक आवेदन पत्र पर ही आवेदन स्वीकार किये जायेंगें। आवेदन जिस सत्र के प्रशिक्षण हेतु किया गया है, उस सत्र के लिये ही मान्य होगा। पूर्व प्रचलित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें। आवेदन पत्र के साथ अन्य आवश्यक सुसंगत दस्तावेज संलग्न होना चाहिए। आवेदन का निर्धारित प्रारूप एवं अन्य जानकारी प्राचार्य शासकीय लेखा प्रशिक्षण शाला रायपुर, से प्राप्त किए जा सकते है। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं निर्देश संभाग के समस्त जिला कोषालायों के सूचना पटल पर अवलोकन किये जा सकते हैं।

प्राकृतिक आपदा पीड़ित 3 परिवार को दी गई 12 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि

जगदलपुर, एजेंसी । कलेक्टर हरिस एस. द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत् प्राकृतिक आपदा पीड़ित 03 परिवार को 12 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई है। जिसके तहत् तहसील जगदलपुर के ग्राम आसना तामाकोनी पारा की निवासी रामबती बघेल की मृत्यु पानी में डूबने से पति सोनाधर बघेल को, तहसील बस्तर के ग्राम भरवांपदर निवासी विकास नाग की मृत्यु पानी में डूबने से पिता सहादेव को और तहसील बास्तानार के ग्राम सांवगेल बीजापार निवासी माहरू मंडावी की मकान गिरने से हुई मृत्यु पर पत्नी चैती को चार-चार लाख रूपए की सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है।

प्राकृतिक आपदा में जनहानि के एक मामले में प्रभावित परिजन हेतु 4 लाख की राशि स्वीकृत

जशपुरनगर, एजेंसी। कलेक्टर रोहित व्यास ने प्राकृतिक आपदा में जनहानि के एक मामले में प्रभावित परिजन को आर.बी.सी. 6-4 के तहत् 04 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि की स्वीकृत दी है। कुनकुरी तहसील अंतर्गत ग्राम ढोढ़ीडांड़, निवासी स्व. मंजित कुजूर का कुआं के पानी में डूबने से 11 नवम्बर 2024 को मृत्यु हो गई। मृतक के निकटतम वारिस उनके पत्नी वंदना कुजूर हेतु 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

जिलों के विद्यालयों में मनाया जा रहा रजत जयंती महोत्सव

दंतेवाड़ा, एजेंसी। छत्तीसगढ़ स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत महोत्सव वर्ष 2025-26 का आयोजन पूरे प्रदेश में बड़े ही उत्साह के साथ किया जा रहा है। यह आयोजन 15 अगस्त 2025 से प्रारंभ होकर 6 फरवरी 2026 तक चलेगा। इसी तारतम्य में स्कूल शिक्षा विभाग, समग्र शिक्षा जिला दंतेवाड़ा के अंतर्गत सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में 28 अगस्त से 7 सितम्बर तक विशेष पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का संचालन जिला शिक्षा अधिकारी एस.के. अम्बस्त एवं डीएमसी हरीश गौतम के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। पखवाड़े की शुरुआत 28 अगस्त को जिले के समस्त विद्यालयों एवं कार्यालयों में पुस्तक वाचन कार्यक्रम से हुई, जिसमें छात्र-छात्राओं के साथ पालक, समुदाय, शिक्षक एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। 29 अगस्त को स्पीड रीडिंग गतिविधि आयोजित हुई, जिसमें विद्यार्थियों और पालकों ने समझ के साथ तेज गति से पढ़ने की प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। 30 अगस्त को विद्यालय विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें समुदाय, पालक एवं विद्यार्थियों ने सक्रिय योगदान दिया।

31 अगस्त को भूतपूर्व छात्रों के साथ एलुमनी बैठक का आयोजन किया गया। इसके बाद 1 सितम्बर को एनईपी 2020 पर आधारित क्विज प्रतियोगिता ने विद्यार्थियों को नई शिक्षा नीति की गहराई से जानकारी देने का अवसर प्रदान किया। 2 सितम्बर को जिले के विभिन्न विद्यालयों में छत्तीसगढ़ का इतिहास विषय पर निबंध प्रतियोगिता एवं मेरे सपनों का विद्यालय विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रजत जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित यह विशेष पखवाड़ा 7 सितम्बर तक चलेगा, जिसमें विभिन्न शैक्षिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों में रचनात्मकता, ज्ञान और प्रदेश के प्रति गर्व की भावना का संचार किया जा रहा है।

स्वास्थ्य और शिक्षा सहित जिले के विकास में हो डीएमएफ की राशि का सदुपयोग

कोंडागांव, एजेंसी। जिला खनिज संस्थान न्यास और जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई, जिसमें बस्तर सांसद महेश कश्यप, कांकेर सांसद भोजराज नाग, बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष और कोंडागांव विधायक लता उसेंडी और विभिन्न जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

बैठक में डी एम एफ की राशि का समुचित उपयोग जिले के निवासियों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सहित क्षेत्र के विकास कार्य में व्यय पर जोर दिया गया। वहीं किसानों को उचित मूल्य पर खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने और जल जीवन मिशन के कार्यो में गुणवत्ता लाने हेतु संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया। इस दौरान कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना, पुलिस अधीक्षक वाय अक्षय कुमार सहित जिला पंचायत अध्यक्ष रीता शोरी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। सांसद महेश कश्यप ने कहा कि जिले में स्कूल

आंगनबाड़ी भवन के मरम्मत या नए भवनों के कार्यो को प्राथमिकता दें। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए यह बहुत जरूरी है। उन्होंने धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत शीघ्र सभी विभागों से प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया। साथ ही आदि कर्म योगी अभियान के क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने सांसद खेल महोत्सव के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंशानुरूप खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियान के तहत राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया जा रहा है, जो कि तीन माह तक चलेगा। सांसद भोजराज नाग ने कहा कि डीएफएम की राशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करें। दुरूपयोग न हो जिले के शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सदुपयोग करें।

कोंडागांव विधायक उसेंडी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई का समुचित उपयोग के निर्देश दिए। किसानों को नर्सरी विकसित करने हेतु प्रशिक्षण दिलाएं। केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा दौरान कहा कि आवास निर्माण में प्रगति लाने जनप्रतिनिधि भी आगे आएं। साथ माओवाद पीड़ित और प्रभावितों के लिए स्वीकृत आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण कराएं।

बैठक में कृषि विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया कि किसानों को खाद उचित मूल्य पर उपलब्ध हो यह सुनिश्चित करें। जिले में जल जीवन मिशन के प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए लोक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया कि जल जीवन मिशन के कार्यों में गुणवत्ता लाएं और गांव के शत प्रतिशत घरों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करें। महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए जिले में कुपोषण को दूर करने हेतु स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहभागिता से अभियान चलाने की बात कही गई। स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान जिले में स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति की जानकारी लेते हुए मलेरिया मुक्त अभियान के लिए जनजागरुकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। जिले में शिक्षा विभाग के स्कूल भवनों की स्थिति की गहन समीक्षा की गई और मरम्मत और नए भवन हेतु प्रस्ताव भेजने को कहा गया। साथ आश्रम छात्रावासों में सभी व्यवस्था दुरुस्त करने तथा कन्या छात्रावासों में सीसीटीवी और महिला सुरक्षा गार्ड एवं स्वास्थ्य कर्मी की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। जनप्रतिनिधि भी आश्रम छात्रावासों का नियमित निरीक्षण करें।

बैठक में इसके अलावा मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, लखपति दीदी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, संसद आदर्श ग्राम, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, भारत नेट, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ग्राम सड़क योजना, केशकाल बायपास सहित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन और निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।

फिंगेश्वर वितरक शाखा नहर के माध्यम से गांव के अंतिम छोर तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जा रहा

गरियाबंद, एजेंसी। जिले के फिंगेश्वर वितरक शाखा नहर के माध्यम से अंतिम छोर के ग्रामों जैसे- पाली, सिरीं, पेंड्रा व रोबा के किसानों को खरीफ फसल सिंचाई के लिए पानी दिया जा रहा है। जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता एस. के. बर्मन के मार्गदर्शन मे छुरा व पाण्डुका अनुविभागीय अधिकारियों एवं पुलिस प्रशासन के प्रयास एवं पेंड्रा पंचयात के सरपंच मिथलेश साहू एवं पाली पंचायत के उपसरपंच चम्पू मारकंडे के साथ किसानों के प्रयास से अंतिम छोर तक पानी पहुंचाया जा रहा है। जल संसाधन विभाग द्वारा क्षेत्र के किसानों से अपील की गई है कि पानी का सही उपयोग करे, व्यर्थ बर्बाद ना करे, नहरों मे बेवजह अवरोध उत्पन्न कर क्षतिग्रस्त न करे।

नागपुर, पाराडोल रेलवे हॉल्ट सर्वे को लेकर बैठक हुई संपन्न, कलेक्टर ने कहा- रेलवे परियोजना में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी

नागपुर-पाराडोल रेलवे हॉल्ट भूमि अधिग्रहण और संयुक्त मापन सर्वेक्षण पर हुई विस्तृत चर्चा

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। जिले में रेलवे परियोजनाओं की प्रगति और समन्वय को लेकर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डी. राहुल वेंकट की अध्यक्षता में आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसडीएम मनेंद्रगढ़, तहसीलदार मनेंद्रगढ़, रेलवे विभाग की टीम सहित वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और सीएसपीडीसीएल के अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने रेलवे विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि रेलवे परियोजना क्षेत्रीय विकास और नागरिक सुविधा दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में नागपुर, पाराडोल रेलवे हॉल्ट परियोजना से संबंधित भूमि अधिग्रहण और संयुक्त मापन सर्वेक्षण रिपोर्ट की रूपरेखा पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

इसमें भूमि स्वामियों का विवरण, अधिसूचना क्रमांक, भू-खण्ड वर्गीकरण, कृषि भूमि का प्रकार, सिंचित व असिंचित रकबा, फसलों की स्थिति और भूमि की स्थिति को स्पष्ट करने पर बल दिया गया। अधिग्रहण के लिए निर्धारित प्रारूप में भूमि स्वामी, पटवारी, राजस्व निरीक्षक, अधिग्रहण एजेंसी तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों के हस्ताक्षर अनिवार्य किए गए हैं। इसी क्रम में निर्मित संपत्तियों का सर्वेक्षण प्रारूप भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें भवनों का प्रकार, निर्माण सामग्री, भवन की आयु, सुपर बिल्ट अप एरिया, अपूर्ण या निर्माणाधीन भवनों का विवरण तथा भू-खण्ड में स्थित अन्य परिसंपत्तियों जैसे ट्यूबवेल, पंप, पक्का कुआं, तालाब, बाउंड्री वॉल आदि का उल्लेख शामिल है। इसके साथ ही उद्यानिकी और वन विभाग की उपस्थिति में फलदार व इमारती वृक्षों का भी विस्तृत मापन, वृक्ष की आयु, चौड़ाई और क्रमांक दर्ज करने का प्रारूप तय करने के निर्देश दिए गए। प्रभावित गांवों को लेकर कलेक्टर ने कहा कि बंजी, सरोला, चिरई पानी, सरभोका, चिताझोर और पाराडोल इन छह गांवों में एक-एक सप्ताह का समय निर्धारित कर कैम्प लगाकर सर्वे किया जाएगा। इस दौरान संबंधित विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि प्रत्येक हितग्राही का सर्वे कर उसका फोटो और वीडियो तैयार कर अलग-अलग फोल्डर में संकलित किया जाए और यह समस्त रिकॉर्ड एसडीएम को उपलब्ध कराया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सर्वे कार्य के समय जनपद सीईओ, सरपंच और सचिव की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए ताकि पारदर्शिता और विश्वास के साथ अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो सके।

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय चिरमिरी की सर्वप्रिय दास ने राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा मे चयनित

मीडिया ऑडीटर, चिरमिरी, (निप्र)। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा 2024-25 में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय चिरमिरी की मेधावी छात्रा सर्वप्रिय दास का चयन हुआ है । छात्रवृत्ति परीक्षा उतीर्ण होकर चयनित होने से छात्रा को शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति प्रदाय होगी । इसके साथ ही सर्वप्रिय दास ने हाल ही में आयोजित कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा में भी सर्वोत्तम अंक प्राप्त कर अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता का परिचय दिया है। सर्वप्रिय दास की इस उपलब्धि ने न केवल विद्यालय का मान बढ़ाया है बल्कि जिले का भी नाम रोशन किया है। उनकी मेहनत, लगन एवं शिक्षकों के मार्गदर्शन का यह प्रतिफल है।

संस्था के प्राचार्य डां.डी.के.उपाध्याय ने छात्रा के इस सफलता पर गर्व व्यक्त किया है तथा सर्वप्रिय को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना दिया हैं। प्राचार्य ने बताया की यह सफलता अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगी।

सड़क सुरक्षा विषयक वाद-विवाद प्रतियोगिता हुई संपन्न, विजेताओं को चेक और प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। भरतपुर में सड़क सुरक्षा विषयक वाद-विवाद प्रतियोगिता संपन्न, विजेताओं को चेक और प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित सड़क सुरक्षा और जीवन रक्षा की महत्ता पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विगत 23 अगस्त 2025 को स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल भरतपुर के ऑडिटोरियम हॉल में विकासखंड स्तरीय वाद-विवाद प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विकासखंड के विभिन्न स्कूलों में जैसे शा.उ.मा.वि. भरतपुर, कुँवारपुर, कंजिया, कन्या उ.मा.वि. जनकपुर, शा. हाई स्कूल खमरौध, सेजेस भरतपुर, न्यू लाइफ इंग्लिश स्कूल जनकपुर तथा वंदना शिक्षा निकेतन जनकपुर के कुल 24 विद्यार्थियों ने सड़क सुरक्षा-जीवन रक्षा विषय पर पक्ष और विपक्ष में प्रभावशाली विचार प्रस्तुत किए।

निर्णायक मंडल द्वारा परिणाम घोषित किए जाने पर सेजेस भरतपुर के छात्र शिवेन्द्र तिवारी प्रथम, न्यू लाइफ इंग्लिश स्कूल जनकपुर के छात्र आर्जव जैन द्वितीय और वंदना शिक्षा निकेतन जनकपुर की छात्रा कु. नव्या गुप्ता तृतीय स्थान पर रहीं। वहीं सेजेस भरतपुर के छात्र हंसल शर्मा, कन्या उ.मा.वि. जनकपुर की छात्रा कु. अर्पिता तिग्गा और उ.मा.वि. कंजिया के छात्र अरविन्द कुमार वर्मा को सांत्वना पुरस्कार के लिए चुना गया।

नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म से आम जनता को मिलेगी बड़ी राहत : भावना

पंडरिया, एजेंसी। जीएसटी कार्उंसिल की 56वीं बैठक में बुधवार को लिए गए ऐतिहासिक फैसलों को लेकर पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म न सिर्फ कारोबारियों बल्कि आम जनता के लिए भी राहत लेकर आया है और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

उन्होंने कहा कि जीएसटी कार्उंसिल की बैठक में यह तय हुआ कि अब सिर्फ दो जीएसटी स्लैब रहेंगे 5त्न और 18त्न. यानी 12त्न और 28त्न स्लैब खत्म हो जाएंगे। केंद्र सरकार के इस फैसले से रोजमर्रा के सामान सस्ते होंगे और जीवन रक्षक दवाओं को टैक्स से पूरी तरह बाहर कर दिया गया है। भावना बोहरा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में कटौती से आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ होगा। व्यापक सुधार हमारे नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाएंगे और सभी के लिए, विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और व्यवसायों के लिए व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने आगे कहा कि वोकल फ़ॉर लोकल जैसे राष्ट्रव्यापी अभियान के माध्यम से एक ओर स्थानीय कारोबार को प्रोत्साहन देने, देश की अर्थव्यवस्था को गति देने एवं स्थानीय विक्रेताओं, कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयास के बाद यह निर्णय देश के विकास को नई गति देगा नेक्स्ट-जेन जीएसटी सुधार देश के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आएगा। इस निर्णय से आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएँ, शिक्षा से संबंधित सामग्री, स्वास्थ्य सेवाएँ तथा कृषि उपयोगी सामान अधिक किफ़ायती होंगे। इसके परिणामस्वरूप आमजन का दैनिक जीवन सरल होगा और

उनकी आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं का सुलभ होना समाज की बड़ी आबादी को सीधे राहत प्रदान करेगा, वहीं कृषि क्षेत्र को भी आवश्यक उपकरण एवं सामग्री की सस्ती उपलब्धता से लाभ होगा, जिससे उत्पादन क्षमता और किसानों की आय दोनों में वृद्धि की संभावना है। साथ ही, उद्योग एवं व्यापार जगत को भी इस सुधार से सहूलियत प्राप्त होगी, जो समग्र आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करेगी।

भावना बोहरा ने कहा कि यह निर्णय कर प्रणाली को अधिक सरल और व्यावहारिक बनाता है तथा पारदर्शिता को भी सुदृढ़ करता है। इससे कर संरचना में स्थिरता आएगी और उपभोक्ता, व्यापारी एवं किसान-सभी को समान रूप से लाभ मिलेगा। यह सुधार केवल राजस्व व्यवस्था तक सीमित न रहकर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ठोस प्रगति का आधार बनेगा और देश की विकास यात्रा को और सुदृढ़ करेगा। अब टैक्स के केवल 5त्न और 18त्न के 2 ही स्लैब होंगे। स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी खत्म करने का निर्णय भी स्वागतयोग्य है। बैठक में हुए फैसलों से अनेक आवश्यक वस्तुओं के दाम कम हो जाएंगे। इसका फायदा गरीब व मध्यमवर्गीय परिवार से लेकर हर छोटे-बड़े उद्यमी को होगा। भावना बोहरा ने कहा कि यह निर्णय पूरी तरह आम आदमी की रोजमर्रा जरूरतों में उपयोगी वस्तुओं में राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है।हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, साबुन, टूथब्रश, साइकिल, टेबलवेयर और अन्य घरेलू सामान 5त्न जीएसटी के दायरे में आएंगे।भारतीय ब्रेड को जीएसटी से छूट दी गई है और अब उन पर पहले की 5त्न की दर से कोई कर नहीं लगेगा। नमकीन, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, कॉफी, मक्खन, घी, कॉर्नफ्लेक्स और चॉकलेट जैसे पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर भी कम दर से कर लगेगा। 350 सीसी तक की छोटी कारों और मोटरसाइकिलों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा वहीं सभी ऑटोमोबाइल पार्ट्स पर 18 फीसदी टैक्स। सीमेंट पर जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया है जिससे अपना घर बनाने में लागत कम होगी। वहीं स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु 33 जीवनरक्षक दवाओं पर जीएसटी 12त्न से शून्य और 3 दवाओं पर 5त्न से शून्य कर दिया है। ये बदलाव गरीब परिवारों के लिए दवा की पहुंच आसान बनाएंगे।व्यक्तिगत जीवन बीमा और व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा सेवाओं पर से जीएसटी खत्म करने का फैसला किया गया है। यह गरीब-हितैषी और विकासोन्मुखी निर्णय है।

कुरेल नदी के पुल पर पानी, रतलाम-खाचरौद मार्ग बंद

पानी से भरे अंडरब्रिज में स्कूल बस उतारी

रतलाम, (एजेंसी)। रतलाम शहर समेत जिले में एक दिन मंगलवार को बारिश थमने के बाद बुधवार फिर से बारिश शुरू हो गई। सुबह से रुक-रुक रिमझिम तो कभी तेज बारिश होती रही। दोपहर बाद तेज मूसलाधार बारिश से रतलाम-खाचरौद मार्ग स्थित कुरेल नदी की रपटे पर पानी आ गया। जिससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन लग गई।

कुछ वाहन चालक जान जोखिम में डालकर पुल पार करते नजर आए। 4 सितंबर को भारी बारिश के अलर्ट के चलते कलेक्टर राजेश बाथम ने कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है।

बाजार में पानी भरा: रतलाम जिले में बारिश का कहर जारी है। बुधवार दोपहर तीन बजे बाद हुई बारिश से बांगरोद गांव के बाजार में नदी का नजारा हो गया।

गांव में स्थित खाटू श्याम बर्बरीक मंदिर पर एकादशी के कारण भक्तों को पानी के बीच ट्रैक्टर में बैठाकर छोड़ा गया। गांव के बाजार में पानी ही पानी नजर आया।

रतलाम खाचरौद रोड बंद: गांव मलवासा से गुजर रही रतलाम-खाचरौद मार्ग पर कुरेल नदी के पुल के ऊपर पानी आ गया। दोपहर 4 बजे से यह मार्ग बंद करना पड़ा। कुछ लोग जान जोखिम डाल अपने वाहन पानी में लेकर निकालते रहे। शाम 7 बजे पुल पर ओर ज्यादा पानी आ गया। ग्रामीणों के मुताबिक रात 12 बजे बाद ही पुल से पानी उतरने की संभावना है। रतलाम शहर में भी बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव हो गया।

पानी भरे अंडरब्रिज में उतारी स्कूल बस

ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश के कारण रेलवे अंडर ब्रिज में भी पानी भर गया। जड़वासा कला व बांगरोद गांव के बीच रेलवे अंडरब्रिज पर पानी भर गया। लाल निशान से ऊपर पानी था। फिर भी बांगरोद के एक प्राइवेट स्कूल के बस चालक ने बस को पानी में उतार दिया। बस में स्टूडेंट बैठे हुए थे। कई लोग अपनी जान जोखिम में अपने वाहन पानी में से निकालते रहे।

कल नर्सरी से 8 वीं तक के स्कूलों की छुट्टी

बारिश के कारण अतिवृष्टि होने और 4 सितंबर को हेवी रेन के अलर्ट के चलते रतलाम कलेक्टर राजेश बाथम ने कक्षा नर्सरी से 8वीं तक शुक्रवार को 4 सितम्बर को स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। जिले के में संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय, सीबीएसई, आईसीएसआई, माध्यम शिक्षा मंडल एवं समस्त बोर्ड से संबंध स्कूलों में छुट्टी रहेगी। शिक्षक अपने निर्धारित समय पर स्कूल में मौजूद रहेंगे। कक्षा 9वीं से 12 वीं तक की त्रैमासिक परीक्षा के चलते पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार संचालित होगी।

रॉयल्टी एक्सपायर रेत के डंपर को कलेक्टर ने छोड़ा

खनिज इंस्पेटर ने लगाई थी पेनल्टी, रेत कारोबारियों ने विधायक पति का स्वागत किया

खंडवा, (एजेंसी)। खंडवा शहर में तीन दिन पहले रॉयल्टी अवधि समाप्त होने के बाद भी रेत का परिवहन कर रहे डंपर को खनिज विभाग ने जब्त कर लिया। कार्रवाई के दौरान रेत कारोबारी और खनिज इंस्पेक्टर आमने-सामने आ गए। विवाद उस समय और बढ़ गया जब भाजपा विधायक कंचन तनवे के पति मुकेश तनवे भी मौके पर पहुंच गए और कार्रवाई का विरोध किया। हालांकि इसके बावजूद खनिज इंस्पेक्टर ने साढ़े चार लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए केस दर्ज किया। बाद में कलेक्टर कोर्ट के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ और डंपर को छोड़ दिया गया।

रॉयल्टी समाप्त, फिर भी जारी था रेत का परिवहन

घटना सोमवार को सिविल लाइन क्षेत्र की है। खनिज निरीक्षक कंचन दांडेकर ने कार्रवाई करते हुए एक डंपर (MP47H7222) को रोका, जिसमें 24 घनमीटर रेत भरी हुई थी। जांच में सामने आया कि डंपर की रॉयल्टी 31 अगस्त की दोपहर 3:30 बजे तक ही वैध थी, जबकि यह डंपर 1 सितंबर की सुबह 11 बजे तक उसी रॉयल्टी पर रेत परिवहन करता पाया गया। खनिज निरीक्षक ने इस पर कुल 4 लाख 45 हजार रुपए की पेनल्टी प्रस्तावित की–जिसमें 15 गुना रॉयल्टी जुर्माना 45 हजार और 4 लाख रुपए पर्यावरण क्षतिपूर्ति शामिल थी। इसके बाद डंपर को कोतवाली थाने में खड़ा करवा दिया गया।

विवाद में पहुंचे विधायक पति, फिर भी दर्ज हुआ मामला

जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, रेत कारोबारी दीपेश बिश्नोई ने तत्काल क्षेत्रीय रेत कारोबारियों के जरिए विधायक कंचन तनवे के पति मुकेश तनवे को मौके पर बुलवा लिया। मुकेश तनवे ऑटो से घटनास्थल पर पहुंचे और खनिज निरीक्षक से तीखी बहस तक हो गई। इसके बावजूद खनिज निरीक्षक ने नियमों के तहत कार्रवाई जारी रखी और केस दर्ज कर दिया। मामला गरमाया तो वरिष्ठ नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया।

डंपर मालिक ने कोर्ट में दी सफाई, पेश किए GPS साक्ष्य

डंपर मालिक दीपेश बिश्नोई ने कलेक्टर कोर्ट में जवाब प्रस्तुत करते हुए बताया कि डंपर खंडवा रेत मंडी 31 अगस्त को ही निर्धारित समय में पहुंच गया था। बारिश और व्यापार में मंदी के कारण गाड़ी खाली नहीं हो सकी, इसलिए डंपर 1 सितंबर की सुबह तक वहीं खड़ा रहा। उन्होंने अपने पक्ष में GPS लोकेशन के साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि गाड़ी ने रॉयल्टी की दूसरी बार उपयोग नहीं किया, बल्कि वह पहली रॉयल्टी की समय सीमा में ही गंतव्य तक पहुंच गई थी।

कलेक्टर कोर्ट ने GPS डेटा के आधार पर डंपर को छोड़ा

कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने खनिज विभाग के प्रतिवेदन और डंपर मालिक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया। उन्होंने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि जीपीएस डाटा से यह प्रमाणित होता है कि डंपर समय सीमा में गंतव्य तक पहुंच चुका था और पूर्व में प्राप्त रॉयल्टी का दोबारा उपयोग नहीं किया गया। ऐसे में वाहन को मुक्त किया जाता है। जैसे ही डंपर थाने से छोड़ा गया, रेत कारोबारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने विधायक पति मुकेश तनवे का माला पहनाकर स्वागत किया।

शिप्रा का जलस्तर बढ़ा, उज्जैन के रामघाट में डूबे मंदिर

गुंबद तक पहुंचा पानी, छोटा ब्रिज भी डूबा, कई इलाकों में जलभराव

उज्जैन,(एजेंसी)। बीती रात से लगातार हो रही तेज बारिश के कारण शिप्रा नदी उफान पर आ गई है। नदी के बढ़ते जलस्तर से रामघाट और दत्त अखाड़ा घाट पर स्थित सभी मंदिर जलमग्न हो गए हैं। वहीं, शहर के कई निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

बुधवार शाम से उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों देवास, इंदौर में रुक-रुक कर तेज बारिश होती रही। बीती रात उज्जैन में 3.36 इंच बारिश दर्ज की गई, जिससे अब तक शहर में कुल 25 इंच बारिश हो चुकी है।

कई इलाकों में जलभराव, प्रशासन अलर्ट पर: बारिश के कारण शहर के बहादुरगंज, एटलस चौराहा, केडी गेट, नीलगंगा, इंदौर गेट, दशहरा मैदान सहित कई क्षेत्रों में जलभराव हो गया है। इन क्षेत्रों के रहवासी जलभराव के कारण खासे परेशान नजर आ रहे हैं।मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक और बारिश होने की संभावना जताई है।

छोटा ब्रिज डूबा, घाटों पर सुरक्षा बढ़ाई गई: शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण उज्जैन-बड़नगर मार्ग स्थित छोटा ब्रिज पूरी तरह से डूब गया है। एहतियात के तौर पर पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया है।

रामघाट पर नगर निगम, होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं को घाट से दूर रखा जा रहा है ताकि किसी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके।

2 तेंदुए जंगल से बाहर, स्कूलों की छुट्टी नर्मदापुरम में एक ने किया मुर्गों का शिकार

3 बार रेस्यू के बाद लौट रहा दूसरा तेंदुआ

नर्मदापुरम, (एजेंसी)। नर्मदापुरम जिले में इन दिनों तेंदुओं की दहशत है। अलग-अलग स्थानों पर 3 तेंदुए रहवासी क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। पथरौटा स्थित पावर ग्रिड परिसर में मादा तेंदुआ और उसके शावक 8 दिनों से घूम रहे हैं। एक शावक की करंट से मौत के बाद रहवासी और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे डर रहे हैं। स्कूल प्रबंधन ने 4 से 13 सितंबर तक छुट्टी घोषित कर दी है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री केंद्रीय विद्यालय कैंपस में भी एक तेंदुआ का 5 दिनों से घूम रहा है।

इसके अलावा एसटीआर का खूंखार तेंदुआ जंगल से बार-बार बाहर आकर रहवासी क्षेत्र में पहुंच उत्पात मचा रहा है। तेंदुआ तवा बफर रेंज के धांसई में 3 दिनों से घुसकर ग्रामीणों की मुर्गे-मुर्गियों को शिकार बना रहा है। ग्रामीण रात में बाहर निकलने से डर रहे हैं। तेंदुआ के मूमेंट से एसटीआर ने उसे पकड़ने के लिए फिर से बुधवार शाम को दो पिंजरे लगा दिए हैं।

ग्रामीण के चूल्हे तक पहुंच गया तेंदुआ: जानकारी के अनुसार, धांसई गांव में दिखा तेंदुआ पहले 19 जून को सिंघानामा के पास से पकड़ा गया था। इसे चूरना के जंगल में छोड़ा गया था। इसके बाद 26 जुलाई को बासनिया गांव में यह एक ग्रामीण के घर की रसोई में जा पहुंचा था, तब भी उसे भगाकर जंगल में लौटाया गया था।

करीब 15 दिन बाद यह फिर से सात गांवों हिरणचापड़ा, खखरापुरा, सहेली आदि में देखा गया, जहां यह लगातार पालतू जानवरों का शिकार कर रहा था। 23 अगस्त को इसे खखरापुरा के पास लगे पिंजरे में तीसरी बार पकड़ा गया था। इसके बाद उसे एक और घने जंगल में छोड़ा गया, लेकिन अब फिर यह बफर जोन के रहवासी इलाकों में दिखाई दे रहा है।

धांसई गांव में लगा पिंजरा, पगमार्क से पुष्टि: ग्रामीणों की शिकायत के बाद बुधवार को एसटीआर की टीम ने धांसई गांव में सर्चिंग की। इस दौरान तेंदुए के पगमार्क मिले, जिसके बाद बुधवार शाम को गांव के रास्तों पर दो पिंजरे लगाए गए हैं। एसटीआर की टीम गांव में गश्त कर रही है और ग्रामीणों को रात में अकेले बाहर न निकलने की सलाह दी जा रही है।

शावक की मौत के बाद आक्रामक है तेंदुआ: इटारसी के पथरौटा स्थित पावर ग्रिड परिसर में भी तेंदुए की हलचल से दहशत है। यहां एक मादा तेंदुआ दिखाई दी है और उसके शावक की मौत के बाद उसके आक्रामक होने की आशंका जताई जा रही है। इस खतरे को देखते हुए टैगोर विद्या मंदिर स्कूल को 4 से 13 सितंबर तक बंद कर दिया गया है। स्कूल में अब ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही हैं।

सागर में जलविहार के लिए कंधों पर लेकर निकले विमान; 125 साल पुरानी है परंपरा

भगवान राधा-कृष्ण की झांकी निहारने उमड़े भक्त

सागर, (एजेंसी)। डोल ग्यारस पर्व पर बुधवार को नगर देवरी में राधा-कृष्ण की भव्य झांकियों और पारंपरिक विमानों की शोभायात्रा निकाली गई। चौरसिया और कोष्टी समाज द्वारा निकाले गए तीन अलग-अलग विमानों को भक्तों ने कंधों पर उठाकर जलबिहार के लिए नगर भ्रमण कराया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी और पूरा शहर भक्ति-भाव में डूबा नजर आया।

125 साल पुरानी है विमान यात्रा की परंपरा: चौरसिया समाज के वरिष्ठजनों ने बताया कि डोल ग्यारस पर विमान निकालने की परंपरा नगर में करीब 125 वर्षों से चली आ रही है। प्रारंभ में लकड़ी से बने विमान उपयोग में लाए जाते थे, जिनमें रामधुन मंडली भी शामिल रहती थी।बाद में लकड़ी का विमान खराब हो जाने पर समाज ने पीतल के विमान का उपयोग शुरू किया। यह विमान चौरसिया धर्मशाला से शुरू होकर खेड़ापति मठ चौराहा पहुंचा, जहां कोष्टी समाज के दो विमान शोभायात्रा में सम्मिलित हुए।

नगर में निकली शोभायात्रा, हुआ जलविहार: तीनों विमानों की शोभायात्रा नगर पालिका चौराहा, बड़ा बाजार, सुखचैन नदी के पुल होते हुए आगे बढ़ी। पुल पर पूजा-अर्चना और जलबिहार की विधि पूरी की गई, जिसके बाद तीनों विमान अपने-अपने स्थलों की ओर वापस लौटे। रात करीब 9 बजे चौरसिया धर्मशाला में शोभायात्रा का समापन हुआ। इसके बाद हवन, पूजन और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम देर रात तक चलता रहा।चौरसिया समाज के विमान की साज-सज्जा परंपरागत रूप से रूपचंद चौरसिया के निवास पर की जाती है, जबकि समापन रमेश चौरसिया के यहां हवन और पूजन के साथ होता है। इस धार्मिक आयोजन में पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा को आज भी श्रद्धा और भक्ति भाव से निभाया जा रहा है।

कोष्टी समाज ने भी निभाई परंपरा: कोष्टी समाज ने भी डोल ग्यारस के दिन विमान निकालने की परंपरा को जीवित रखा है। दोनों समाजों के विमानों के मिलन से यह शोभायात्रा और भी भव्य बन गई। आयोजन में शिवराम चौरसिया, गोविंद चौरसिया, दीपक चौरसिया, जगदीश चौरसिया, शंकर चौरसिया, धनीराम चौरसिया, मयंक चौरसिया, वीरेंद्र चौरसिया, हेमंत चौरसिया, मनोज चौरसिया, कल्लू चौरसिया, कैलाश चौरसिया, अनुराग ज्योतिषी, हुकमचंद कैलाश कोष्टी, जमुना कोष्टी, राधे श्याम कोष्टी सहित बड़ी संख्या में नगरवासी शामिल हुए।

श्रद्धा और परंपरा का मिला संगम: शोभायात्रा के दौरान नगर की गलियां राधा-कृष्ण के जयकारों से गूंज उठीं। सजे-धजे विमान, भक्तों की टोली और पारंपरिक गीतों ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। डोल ग्यारस का यह आयोजन सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक बन चुका है, जिसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने के प्रयास लगातार जारी हैं।

दिल्ली पहुंचे धीरेंद्र शास्त्री, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की तैयारी

छतरपुर। दिल्ली के छतरपुर स्थित मां कात्यायनी मंदिर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने चार राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह यात्रा राजनीतिक नहीं, आध्यात्मिक है। बागेश्वर महाराज ने कहा कि उनकी लड़ाई विचारों से है, तलवारों से नहीं। वे जाति अभिमान छोड़ने की बात कर रहे हैं, जाति छोड़ने की नहीं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को मिर्च लगे तो लग जाए मंदिर मस्जिद और गिरजाघर में राष्ट्रगान बजाया जाए भले ही सप्ताह में एक दिन बजाया जाए ताकि देशभक्त और देशद्रोही सामने आए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्यप्रदेश के कार्यकर्ता होंगे

खरगोन में पुलिया से गिरी कार, 4 युवक घायल; धार से गोगांवा झांकी देखने जा रहे थे

सनावद रोड पर हादसा, क्रेन से निकाला वाहन

खरगोन, (एजेंसी)। खरगोन जिले के सनावद रोड पर बुधवार देर रात एक तेज रफ्तार कार (GJ23CB0311) ठीबगांव के पास पुलिया से नीचे नाले में गिर गई। हादसे में कार सवार धार जिले के चार युवकों को मामूली चोट आई हैं। घटना के बाद कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ।

गोगांवा दर्शन के लिए जा रहे थे

जानकारी के अनुसार, यह हादसा रात लगभग 2:15 बजे हुआ जब धार जिले के बेटमा गांव से गोगांवा में झांकियों के दर्शन के लिए निकले चार युवक एक मोड़ पर कार से नियंत्रण खो बैठे। तेज रफ्तार होने के कारण कार पुलिया से सीधे नीचे नाले में जा गिरी।

घायल युवकों की पहचान अर्जुन कुशवाह, विजय कुशवाह, सचिन कुशवाह और कुणाल कुशवाह के रूप में हुई है। सभी को हल्की चोटें आई हैं और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई।

पुलिस मौके पर पहुंची, सुबह निकाली कार

हादसे की सूचना मिलते ही गोगांवा पुलिस मौके पर पहुंच गई। चूंकि कार पुलिया के अंदर फंसी हुई थी, इसलिए गुरुवार सुबह क्रेन की मदद से उसे बाहर निकाला गया। इस दौरान कुछ देर के लिए सनावद रोड पर यातायात बाधित रहा।

कारणों की जांच में जुटी पुलिस

फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और मोड़ पर नियंत्रण खोने की बात सामने आ रही है। हालांकि कोई बड़ी जनहानि नहीं होने से राहत की बात है।

रायसेन के नीमखेड़ा में मिला बुजुर्ग महिला का शव–गले पर चोट के निशान; एसपी समेत फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची

रायसेन। रायसेन के भोपाल रोड स्थित नीमखेड़ा में गुरुवार सुबह एक बुजुर्ग महिला का शव उनके घर में मिला। मृतका की पहचान 65 साल की भंवरी बाई मीणा के रूप में हुई है। महिला के गले पर चोट के निशान मिले हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही एसपी पंकज कुमार पाण्डेय, सैंडोरा चौकी प्रभारी शैलेंद्र दायमा और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। जांच में डॉग स्क्वॉड की भी मदद ली जा रही है। जानकारी के अनुसार, भंवरी बाई अपने घर में अकेली रहती थीं। उनके पति का पहले ही निधन हो चुका था। उनकी तीन बेटियां हैं, जिनकी शादी हो चुकी है। गुरुवार सुबह परिवार का एक युवक जब महिला के कमरे में पहुंचा, तो उन्हें बेसुध पाया। शरीर में कोई हलचल नहीं थी। युवक ने तुरंत पड़ोसियों और गांव के अन्य लोगों को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस को खबर दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

ट्रैक्टर में बंधी मिक्सर मशीन से गिरा बालक, अस्पताल में मौत

अशोकनगर(एजेंसी)। अशोक नगर 7 ट्रैक्टर में बंधी मिक्सर मशीन पर बैठा 15 वर्षीय बालक अचानक नीचे गिर गया, जिससे उसे चोट आ गई। परिजन इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे जहां चेकअप के दौरान डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया।

जानकारी अनुसार आशीष पुत्र शेर सिंह यादव 15 साल निवासी सरसेला स्कूल की यूनिफार्म पहनकर अपने दोस्तों के साथ था। जिला अस्पताल लेकर पहुंचे परिजनों ने बताया कि आशीष सहित अन्य बच्चे एक ट्रैक्टर में बंधी मिक्सर मशीन में बैठ गए थे। करीब 5 से 7 बच्चे बैठे हुए थे। अचानक आशीष गिर गया, जिसके गिरते ही अन्य साथियों ने आवाज दी। उसके परिजनों को बुलाकर इलाज के लिए सेहराई ले जाया गया जहां से जिला अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन बिना पीएम कराए ही उसे ले गए।

अमृतसर का लाल बना टी20 क्रिकेट का बेताज बादशाह

नई दिल्ली,एजेंसी। अभिषेक शर्मा आज अपना 25वां जन्मदिन मना रहे हैं। बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज और उपयोगी स्पिनर के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले अभिषेक का करियर अब तक शानदार उपलब्धियों से भरा रहा है। हालांकि, भारतीय टीम तक का सफर इतना आसान नहीं रहा है। आइए उनकी कहानी जानते हैं... 27 मार्च 2024 की शाम थी। रोशनी से जगमगाते हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में जब सनराइजर्स ने मुंबई इंडियंस का सामना किया, तो दर्शकों की नजरें पहले ट्रेविस हेड पर टिकी थीं। हेड ने महज 18 गेंदों पर अर्धशतक लगाया, लेकिन असली आतिशबाजी तब हुई जब पंजाब के अमृतसर से आए बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा मैदान पर उतरे।सिर्फ 23 गेंदों में सात छक्के और तीन चौकों से मुंबई के दिग्गज गेंदबाजों को चारों खाने चित्त कर दिया। उनकी इस धुआंधार पारी ने न सिर्फ मैच का रुख बदल दिया बल्कि उन्हें देशभर की सुर्खियों में ला खड़ा किया। अभिषेक शर्मा आज अपना 25वां जन्मदिन मना रहे हैं। बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज और उपयोगी स्पिनर के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले अभिषेक का करियर अब तक शानदार उपलब्धियों से भरा रहा है। हालांकि, भारतीय टीम तक का सफर इतना आसान नहीं रहा है। उन्हें कई चुनौतियों और संघर्षों का सामना करना पड़ा है। आइए उनकी कहानी जानते हैं...

अमृतसर की गलियों से क्रिकेट की ओर सफर : अभिषेक शर्मा का जन्म चार सितंबर 2000 को पंजाब के अमृतसर में हुआ। वे तीन भाई-बहनों में सबसे छोटे हैं। उनके पिता राजकुमार शर्मा खुद पंजाब के लिए लेफ्ट-आर्म स्पिनर रह चुके हैं। 1985-86 में अंडर-22 विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल तक उन्होंने टीम का हिस्सा रहते हुए क्रिकेट खेला। मगर परिस्थितियों ने उनका करियर

रोक दिया। दुबई जाकर भी सफलता नहीं मिली तो वे लौटकर बैंक ऑफ इंडिया के लिए खेले और बाद में अमृतसर गेम्स एसोसिएशन के कोच और सेलेक्टर बने। पिता का अधूरा सपना बेटे में पूरा करने का निश्चय उन्होंने किया और यही जुनून अभिषेक की नसों में दौड़ा। महज तीन साल की उम्र में जब बच्चों के खिलौने हाथ में होते हैं, तब अभिषेक प्लास्टिक के बल्ले से शॉट खेलने लगे।

पिता की सीख और बचपन की मेहनत : अभिषेक ने डीपीएस अमृतसर से पढ़ाई की और फिर डीएवी कॉलेज से ग्रेजुएशन। पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन दिल क्रिकेट पर टिका रहा। पिता राजकुमार रोजाना उन्हें प्रैक्टिस के लिए ले जाते। यही मेहनत रंग लाई जब उनका चयन पंजाब अंडर-14 टीम में हुआ। श्रीनगर में हुए अंडर-14 मुकाबले के दौरान महान स्पिनर बिशन सिंह बेदी ने उनकी गेंदबाजी देखी और तारीफ की। बेदी ने कहा कि अभिषेक एक बेहतरीन ऑलराउंडर बन सकते हैं।

रणजी डेब्यू और ऑलराउंड प्रदर्शन : सिर्फ 16 साल की उम्र में अभिषेक ने रणजी ट्रॉफी में कदम रखा। हिमाचल प्रदेश के खिलाफ उन्होंने पहली ही पारी में 94 रन बनाए और एक विकेट भी लिया। हरभजन सिंह ने उन्हें कैप पहनाई और डेब्यू यादगार बना दिया। उस मैच से साफ हो गया था कि यह लड़का आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट का बड़ा नाम बन सकता है।

अंडर-19 का चमकता सितारा : 2016 में अभिषेक को भारतीय अंडर-19 टीम का कप्तान बनाया गया। उनकी कप्तानी में टीम ने इमर्जिंग एशिया कप जीता। हालांकि 2018 अंडर-19 वर्ल्ड कप से पहले कप्तानी पृथ्वी शॉ को मिल गई, लेकिन अभिषेक ने बतौर खिलाड़ी टीम में अहम योगदान दिया। बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने शानदार अर्धशतक जड़ा और गेंदबाजी में भी विकेट निकाले। 2015-16 में विजय मर्चेंट ट्रॉफी में 1200 रन और 57 विकेट लेकर वे पहले क्रिकेटर बने जिन्होंने दो ाज सिंह डूंगरपुर अवॉर्ड जीते।

IPL में धमाकेदार शुरुआत : जनवरी 2018 में दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) ने उन्हें 55 लाख रुपये में खरीदा। उसी साल मई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 19 गेंदों पर 46 रन बना डाले। उस पारी में तीन चौके और चार छक्के थे। स्ट्राइक रेट 242, यानी असली टी20 का स्वाद। उस पारी ने सबका ध्यान उनकी ओर खींचा।

युवराज सिंह का मार्गदर्शन : अभिषेक शर्मा की सफलता में युवराज सिंह का बड़ा हाथ है। पिता राजकुमार शर्मा ने एक इंटरव्यू में बताया था, युवराज सिंह ने अभिषेक की सफलता में बहुत बड़ा रोल निभाया है। उन्होंने उस पर कड़ी मेहनत की है। युवराज ने न सिर्फ तकनीकी सुधार किया बल्कि अभिषेक के लिए अनुशासन की भी नींव रखी। योगराज सिंह (युवराज के पिता) ने बताया कि युवराज ने अभिषेक को समझाया कि देर रात दोस्तों के साथ बाहर न निकलो, समय पर सो जाओ और फिटनेस को प्राथमिकता दो। युवराज अब भी मजाकिया अंदाज में उन्हें टोकते रहते हैं।

एशिया कप में कोरिया के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ के बाद मनदीप सिंह ने कहा, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला

राजगीर, एजेंसी। एशिया कप राजगीर में दक्षिण कोरिया के खिलाफ अपनी टीम के ड्रॉ होने के बाद, बराबरी का गोल करने वाले मनदीप सिंह ने कहा कि टीम गोल स्कोरिंग के मामले में परिणाम हासिल करने में विफल रही और आगामी मैचों में बेहतर प्रदर्शन करने की कसम खाईजबान टीम का पहले मुकाबले में टीम इंडिया से 10 सितंबर को सामना होगा. इसके बाद यूएई की टीम पाकिस्तान और ओमान से अपने मुकाबले खेलेगी. ग्रुप स्टेज में टॉप-2 पर रहने वाली टीम सुपर-4 में जगह बनाएगी और इसके बाद सुपर-4 में टॉप-2 में रहने वाली टीमों के बीच फाइनल खेला जाएगा.यूएई की टीम इन दिनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ अपने घर में टी20 स्ट्राई सीरीज खेल रही है. इसके तुरंत बाद उनकी टीम एशिया कप 2025 में खेलती नजर आएगी. पिछली बार यूएई की टीम ने साल 2016 में एशिया कप में हिस्सा लिया था, जब बांग्लादेश मेजबानी कर रहा था.

भारतीय पुरुष हॉकी टीम और कोरिया ने पुरुष एशिया कप, राजगीर, बिहार 2025 में अपने शुरुआती सुपर 4 गेम में 2-2 से ड्रॉ खेला। भारत के लिए हार्दिक सिंह (8%) और मंदीप सिंह (53%) ने गोल किए, जबकि कोरिया के लिए जिहुन यांग (12%) और ह्योनहोंग किम (14%) ने गोल किए। एएनआई से बात करते हुए, मनदीप ने कहा, मैं टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहता हूं। आखिरकार, मुझे गोल मिल गया। लेकिन यह मेरा लक्ष्य नहीं है। यह हमेशा टीम का लक्ष्य होता है। लेकिन फिर भी, हमने गलतियाँ कीं और परिणाम प्राप्त नहीं कर सके, जो आमतौर पर नहीं होता है। आज, हमें एक बड़ी सीख मिली। हम आगामी मैचों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। हमारा आखिरी स्पर्श नेट तक नहीं पहुंचा, यही वजह है कि हम ड्रॉ रहे। लेकिन हम बैठकर इस बारे में बात करेंगे। बारिश के कारण मैच थोड़ी देरी से शुरू हुआ, लेकिन भारत ने गीली परिस्थितियों में भी कई सर्कल एंट्री और गोल पर सकारात्मक हमलों के साथ शानदार शुरुआत की। उन्होंने क्रमशः दूसरे और सातवें मिनट में दो शुरुआती पेनल्टी कॉर्नर भी हासिल किए, लेकिन गोलकीपर को भेदने में नाकाम रहे।

आठवें मिनट में सुखजीत सिंह ने मिडफील्ड में गेंद हासिल की और उसे हार्दिक सिंह (8%) को दिया, जिन्होंने कोरियाई बैकलाइन को चकमा देते हुए एक अविश्वसनीय एकल दौड़ लगाई और गोलकीपर को छकाते हुए एक आसान फिनिश के साथ स्कोरिंग का खाता खोला। कोरिया ने लगातार दो गोल करके मुकाबले में बढ़त हासिल कर ली। 12वें मिनट में, सर्कल के अंदर जुगराज सिंह के फाउल के कारण कोरिया को पेनल्टी स्ट्रोक दिया गया। जिहुन यांग (12%) ने आगे बढ़कर एक शक्तिशाली शॉट के साथ ऊपरी दाएँ कोने पर बराबरी का गोल दागा। दो मिनट बाद, कोरिया ने एक पेनल्टी कॉर्नर जीता, जिसे ह्योनहोंग किम (14%) के ड्रैगफ्लिक ने सफलतापूर्वक गोल में बदलकर बढ़त हासिल कर ली।

दिग्गज स्पिनर अमित मिश्रा ने 25 साल बाद पेशेवर क्रिकेट को कहा अलविदा

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने गुरुवार को पेशेवर क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। करीब 25 साल लंबे करियर में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले मिश्रा ने कहा कि यह फैसला बार-बार होने वाली चोटों और नई पीढ़ी को मौका देने की सोच के चलते लिया गया है। अपने करियर के दौरान अमित मिश्रा ने भारतीय टीम के लिए कई यादगार स्पेल फेंके। टेस्ट, वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को परेशान किया। आईपीएल में भी वह सबसे सफल गेंदबाजों में शुमार रहे और कई हैट्रिक अपने नाम कीं। मेहनत, अनुशासन और क्रिकेट के प्रति जुनून ने उन्हें लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बना दिया।

रिटायरमेंट पर अमित मिश्रा ने कहा, क्रिकेट के ये 25 साल मेरे जीवन के लिए अविस्मरणीय रहे। मैं बीसीसीआई, प्रशासन, हरियाणा क्रिकेट संघ, सपोर्ट स्टाफ, अपने साथियों और परिवार का दिल से आभारी हूं। खासकर उन फैन्स का धन्यवाद करता हूं, जिनका प्यार और समर्थन मुझे हर जगह मिला। क्रिकेट ने मुझे अनगिनत यादें और अनुभव दिए, जिन्हें मैं जीवनभर संजोकर रखूंगा।

संन्यास के बाद मिश्रा ने संकेत दिए कि वह क्रिकेट से जुड़े रहेंगे। चाहे कोचिंग हो, कमेंट्री या युवा खिलाड़ियों को गाइड करना, वह हर तरह से क्रिकेट को वापस देना चाहते हैं। इसके अलावा, सोशल मीडिया और यूट्यूब पर भी वह सक्रिय रहेंगे और फैन्स के साथ जुड़े रहेंगे। अमित मिश्रा की विरासत सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका अनुभव और समझ आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुमूल्य धरोहर साबित होगी।

एशिया कप से पहलेलगातार तीसरे टी20 सीरीज जीत से उत्साहित हैं लिटन दास

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश टी20 टीम के कप्तान लिटन कुमार दास ने कहा है कि उनकी टीम आगामी एशिया कप के लिए पूरी तरह तैयार है। टूर्नामेंट का आगाज़ 9 सितंबर से यूएई में होने जा रहा है। बांग्लादेश ने हाल ही में नीदरलैंड्स को तीन मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 से हराया। तीसरा मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। यह बांग्लादेश की लगातार तीसरी टी20 सीरीज जीत है। इससे पहले उन्होंने श्रीलंका और पाकिस्तान को हराया था।

लिटन ने टीम की इस सफलता का श्रेय प्री-सीरीज कैंप को दिया। टीम ने पहले ढाका में फिटनेस कैंप लगाया और फिर सिलहट में स्किल कैंप आयोजित किया, जहां बेहतर पिचों पर खिलाड़ियों ने अभ्यास किया। लिटन ने कहा, मुझे लगता है हम एशिया कप के लिए अच्छी तरह तैयार हैं। जो कैंप हमने किया था, वह सिर्फ इस सीरीज के लिए नहीं था, बल्कि एशिया कप को ध्यान में रखकर किया गया था। मैंने पहले कभी इतना अच्छा कैंप नहीं देखा। उन्होंने आगे कहा, फिटनेस तो मीरपुर में भी हो सकती थी, लेकिन जिस तरह की प्रैक्टिस की ज़रूरत थी, वह केवल सिलहट में संभव थी। कुल मिलाकर यह यात्रा हमारे लिए बहुत फायदेमंद रही। लिटन ने इस दौरान खिलाड़ियों को मिले मैच टाइम को भी अहम बताया। एक बार अभिषेक के आउट होने पर उन्होंने कहा, वाह अभिषेक वाहज शानदार पारी, लेकिन जिस शॉट पर आउट हुए, वो क्या ही शानदार था! अब तुम्हारे लिए स्पेशल चप्पल इंतजार कर रही 2024 में अभिषेक का बल्ला आग उगल रहा था। पूरे सीजन में उन्होंने 400+ रन बनाए और स्ट्राइक रेट 180 से ऊपर रहा। उनकी बल्लेबाजी ने स्ना को नई पहचान दिलाई। टीम फाइनल तक पहुंची, लेकिन खिताब से चूक गई। आईपीएल 2024 में अभिषेक ने 16 मैचों में 32.26 की औसत और 204.21 के स्ट्राइक रेट से 484 रन बनाए। इनमें तीन अर्धशतक शामिल हैं। इस सीअमृतसर की गलियों से निकला यह लड़का आज भारतीय क्रिकेट का चमकता सितारा है। मेहनत, अनुशासन, पिता की सीख और युवराज सिंह की मेंटरशिप ने उन्हें बड़ा बनाया। अभिषेक शर्मा अब न सिर्फ आईपीएल के स्टार हैं बल्कि टीम इंडिया में भी लंबी पारी खेलने की क्षमता रखते हैं। जिसे भी खेलने का मौका मिला, उसने अच्छा प्रदर्शन किया। सिर्फ सैफुद्दीन ही कुछ खास नहीं कर पाए। बाकियों ने कम से कम एक मैच में योगदान दिया। प्रैक्टिस जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है मैच में प्रदर्शन करना। मैच खेलने से ही खेल का अनुभव और समझ बढ़ती है। उन्होंने माना कि सभी बल्लेबाज़ों को मौके नहीं मिल पाए, लेकिन इसे सकारात्मक संकेत बताया। यह अच्छी बात है कि हमारे टॉप ऑर्डर ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि मिडिल ऑर्डर को मौका ही नहीं मिला। एशिया कप में वह दिन भी आएगा जब हर किसी को बल्लेबाज़ी करनी होगी, लेकिन फिलहाल यह हमारे लिए सकारात्मक संकेत है।

सीपीएल 2025 : सेंट लूसिया किंग्स ने त्रिनबागो नाइट राइडर्स को 7 विकेट से रौंदा, प्लेऑफ में बनाई जगह

नई दिल्ली, एजेंसी। त्रिनिदाद में खेले गए मुकाबले में बुधवार रात (भारतीय समयानुसार गुरुवार) सेंट लूसिया किंग्स ने हाई-फ्लाइंग त्रिनबागो नाइट राइडर्स को 53 गेंदें शेष रहते 7 विकेट से मात दी। इस जीत के साथ किंग्स नाइट राइडर्स के बाद सीपीएल 2025 प्लेऑफ में क्वालीफाई करने वाली दूसरी टीम बन गई। किंग्स की जीत में उनके स्पिन गेंदबाजों का अहम योगदान रहा। तबरेज़ शम्सी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके, वहीं खारी पियरे और रोस्टन चेज़ ने 2-2 विकेट लेकर विपक्षी बल्लेबाज़ों की कमर तोड़ दी। मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करने उतरी नाइट राइडर्स की शुरुआत बेहद खराब रही। कोलिन मुनरो दूसरे ही गेंद पर पियरे का शिकार बने। डैरेन ब्रावो ने कुछ बड़े शॉट्स लगाए लेकिन जल्द ही आउट हो गए। निकोलस पूरन ने भाग्य का सहारा लेते हुए शुरुआत में बचाव पाया और उसके बाद लगातार दो छक्के जड़े, मगर टीकेआर का पतन जारी रहा। एलेक्स हेल्स पावरप्ले की अंतिम गेंद पर आउट हुए और 6 ओवर की समाप्ति पर टीम 3 विकेट खो चुकी थी। भारत के लिए उन्होंने कई रिकॉर्ड्स बनाए और विराट अभिषेक बल्ले से नए कीर्तिमान रचते गए। आईपीएल 2025 में उन्होंने एक शतक और दो अर्धशतक लगाए। आर्थिक सफलता और अभिषेक की नेट वर्थ 12-15 करोड़ रुपये के बीच है। इसमें बीसीसीआई का ग्रेड-सी अनुबंध (1 करोड़ रुपये वार्षिक), आईपीएल से मोटी

कमाई और ब्रांड एंडोर्समेंट शामिल हैं। आईपीएल 2025 में उनकी कीमत 14 करोड़ रुपये रही। कारों के शौकीन अभिषेक कई महंगी और लग्जरी कारों के मालिक हैं। यह उनकी बढ़ती लोकप्रियता और सफलता का सबूत है।

अभिषेक की कहानी महज क्रिकेट तक सीमित नहीं है। यह उस पिता के सपने की कहानी भी है जो अधूरा रह गया था। राजकुमार शर्मा ने जो रास्ता तय किया था, उसे अब उनके बेटे ने मुकम्मल किया है। अभिषेक न सिर्फ भारतीय क्रिकेट का भविष्य हैं बल्कि युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा भी। इसके बाद शम्सी ने आते ही अकील होसैन को पहली ही गेंद पर पवेलियन भेजा। पूरन भी ज्यादा देर टिक नहीं सके और चेज़ की गेंद पर विकेटकीपर को कैच थमा बैठे। आंद्रे रसेल को शम्सी ने बोल्ड कर नाइट राइडर्स की उम्मीदों को करारा झटका दिया। पोलार्ड भी शम्सी के शिकार बने। अंत में टेरेंस हाइंड्स और नाथन एडवर्ड्स ने टीम को 100 के पार पहुंचाया लेकिन पोटगीटर और अल्जारी जोसेफ ने आखिरी झटके दिए और पूरी टीम 109 पर ढेर हो गई। लक्ष्य का पीछा करते हुए टिम सीफर्ट ने धमाकेदार शुरुआत की। उन्होंने पहले ही ओवर में 14 रन ठोक डाले और तेजी से रन बटोरे। जॉनसन चार्ल्स जल्दी आउट हो गए, लेकिन सीफर्ट और अकीम ऑगस्टे ने मिलकर 40 रन की साझेदारी की। ऑगस्टे ने रसेल की गेंदों पर ताबड़तोड़ प्रहार करते हुए 20 रन लूटे। सीफर्ट 36 रन बनाकर आउट हुए जबकि ऑगस्टे ने भी 28 रन की तेज पारी खेली। अंत में रोस्टन चेज़ और डेविड वीज़ ने टीम को आसानी से लक्ष्य तक पहुंचा दिया।

संक्षिप्त स्कोरकार्ड: त्रिनबागो नाइट राइडर्स – 109/10 (18.1 ओवर) (निकोलस पूरन 30, नाथन एडवर्ड्स 17; तबरेज़ शम्सी 3/12, रोस्टन चेज़ 2/19)

सेंट लूसिया किंग्स – 112/3 (11.1 ओवर) (टिम सीफर्ट 36, अकीम ऑगस्टे 28; सुनील नारायण 2/28, उस्मान तारिक 1/26) परिणाम: सेंट लूसिया किंग्स 7 विकेट से विजयी।

एएफसी एशियन कप क्वालीफायर का भारत बनाम सिंगापुर मैच बेंगलुरु से गोवा शिफ्ट

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का एएफसी एशियन कप 2026 क्वालीफायर ग्रुप-सी मुकाबला अब बेंगलुरु की जगह गोवा में खेला जाएगा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (एआईएफएफ) ने गुरुवार को पुष्टि की कि यह मैच 14 अक्टूबर को फातोर्डा स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा। भारत और सिंगापुर के बीच अक्टूबर की अंतरराष्ट्रीय विंडो में दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच 9 अक्टूबर को सिंगापुर के नेशनल स्टेडियम, काल्लांग में होगा, जिसके बाद दोनों टीमें दूसरे लेग के लिए गोवा रवाना होंगी। यह मुकाबला पहले बेंगलुरु के श्री कांतेरावा स्टेडियम में होना तय था, लेकिन लॉजिस्टिक समस्याओं के चलते इसे शिफ्ट करना पड़ा। कर्नाटक राज्य फुटबॉल संघ के अध्यक्ष एनए हारिस ने कहा, कांतेरावा स्टेडियम का इस्तेमाल एथलेटिक्स समेत कई खेलों के लिए होता है। फुटबॉल मैच के लिए हमें मैदान तैयार करने में समय चाहिए। यह मैच अचानक हमें अलॉट हुआ था। हमें दुख है कि मैच कहीं और शिफ्ट हो गया, लेकिन यह हमारे हाथ में नहीं है। हारिस ने आगे बताया कि बेंगलुरु में जल्द ही एक नया आधुनिक फुटबॉल स्टेडियम तैयार होगा।

गौरतलब है कि भारत अभी तीसरे दौर के क्वालीफायर में जीत से वंचित है। टीम ने पहले बांग्लादेश से 0-0 की ड्रॉ खेली और फिर हांगकांग से 0-1 से हार झेली। यह मुकाबला कोच मनोलो मार्क्वेज़ का आखिरी मैच था, जिसके बाद खालिद जमील ने टीम की जिम्मेदारी संभाली।

यूएस ओपन में यूकी भांबरी ने रचा इतिहास, सेमीफाइनल में बनाई जगह

न्यूयॉर्क, एजेंसी। भारत के टेनिस स्टार यूकी भांबरी ने बुधवार को यूएस ओपन पुरुष युगल स्पर्धा के सेमीफाइनल में जगह बनाकर इतिहास रच दिया। यह उनका पहला ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल है, जिसे उन्होंने न्यूजीलैंड के पार्टनर माइकल वीन्स के साथ मिलकर हासिल किया।

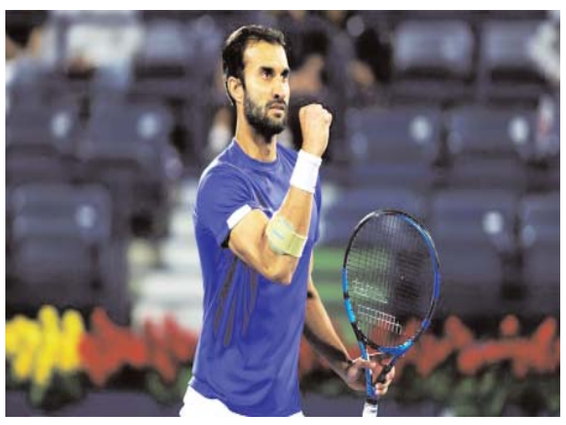

इंडो-कीवी जोड़ी ने क्वार्टरफाइनल मुकाबले में 11वीं वरीयता प्राप्त निकोला मेक्टिक और राजीव राम को 6-3, 6-7(8), 6-3 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। इससे पहले प्री-क्वार्टरफाइनल में भांबरी-वीन्स की जोड़ी ने चौथी वरीयता प्राप्त केविन क्राविएट्ज़ और टिम प्यूट्ज़ को बाहर कर दिया था। 33 वर्षीय भांबरी के लिए यह करियर का सबसे बड़ा मुकाम है। कई सालों तक चोटों से जूझने और सिंगल्स से डबल्स में ट्रांजिशन करने के बाद उन्होंने यह बड़ी सफलता हासिल की। साल 2009 के ऑस्ट्रेलियन ओपन बॉयज़ चैंपियन और पूर्व जूनियर वर्ल्ड नंबर-1 रहे भांबरी ने अब सीनियर स्तर पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया है।

इस जीत के साथ भारत की पुरुष युगल में शानदार परंपरा और आगे बढ़ी है, जहां पहले लिएंडर पेस, महेश भूपति और रोहन बोपन्ना जैसे दिग्गजों ने भी दमदार प्रदर्शन किया था।

क्वार्टरफाइनल में भांबरी और वीन्स ने पहले सेट में शानदार शुरुआत की। भांबरी ने मेक्टिक की सर्विस पर रिटर्न विनर लगाकर ब्रेक हासिल किया और 3-1 की बढ़त बनाई। निर्णायक सेट में 3-3 की बराबरी के बाद मेक्टिक की डबल फॉल्ट से इंडो-कीवी जोड़ी ने बढ़त हासिल की और अंततः 6-3 से मुकाबला अपने नाम किया। अब सेमीफाइनल में भांबरी और वीन्स का सामना ब्रिटेन की छठी वरीयता प्राप्त जोड़ी जो सॉलिसबरी और नील स्कुप्स्की से होगा।

मैहर में शारदेय नवरात्रि मेला 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक

नवरात्रि मेले की व्यवस्था को लेकर बैठक संपन्न

मीडिया ऑडीटर, मैहर (निप्र)। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय मैहर के सभाकक्ष में गुरूवार को सांसद गणेश सिंह और विधायक मैहर श्रीकांत चतुर्वेदी की उपस्थिति में आगामी शारदेय नवरात्रि मेले की व्यवस्था को लेकर विभागीय अधिकारी एवं मां शारदा प्रबंध समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर कलेक्टर रानी बाटड, पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल, अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, एएसपी चंचल नागर, एसडीएम दिव्या पटेल, सीएसपी महेन्द्र सिंह, तहसीलदार जीतेन्द्र पटेल, सीएमओ सुषमा मिश्रा, मां शारदा प्रबंध समिति के पदाधिकारी सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

सांसद सिंह ने कहा कि मैहर जिले के शारदेय नवरात्रि मेले में पूरे देश से लोग श्रद्धा से दर्शन करने आते हैं। नवरात्रि मेले में मंदिर की सजावट और विद्युत सजावट नये स्वरूप में की जाये ताकि श्रद्धालुओं को भक्तिभाव से परिपूर्ण माहौल का अनुभव हो सके। उन्होंने कहा कि मैहर शहर के प्रवेश द्वारों पर चारों ओर सजावट की जाये। मंदिर प्रबंधन समिति के अलावा श्रद्धालुओं के लिए जलपान और अन्य सुविधाओं के लिए स्टाल स्वयं सेवी और सामाजिक संस्थायें लगाये। उन्होंने कहा कि मां के प्रसाद में पन्नी और पॉलीथीन के थैलों के स्थान पर कागज या कपडे के थैले का प्रयोग प्रोत्साहित किया जाये तथा सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुलिस बल के अतिरिक्त स्काउट गाइड, रेडक्रास, एनसीसी और एनएसएस के कैडिटों की भी सेवायें ली सकती है।

कलेक्टर मैहर बाटड ने कहा कि मैहर के नवरात्रि मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां शारदा के दर्शन के लिये मैहर पहुंचेंगे। मां शारदा देवी के कुंवार नवरात्रि मेला में श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखा जाए। उन्होंने बताया कि मेले में लगभग 600 पुलिस बल रहेगा जिनके ठहरने की व्यवस्था यात्री निवास में की गई है। मेले के दौरान मां शारदा मंदिर के गर्भ गृह में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। श्रद्धालुओं को अस्थायी टेंट लगाकर आश्रय की व्यवस्था की जायेगी।

मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को पेयजल के पुख्ता इंतजाम किए जाएं तथा साफ-सफाई रखने हेतु आवश्यक स्थानों पर डस्टबिन रखी जाए। जिससे मेला प्रांगण साफ-स्वच्छ रहे। विद्युत की निर्बाध आपूर्ति रखने तथा कटे-फटे तारों को दुरुस्त करने संबंधी अधिकारियों को निर्देश दिए। तीर्थ यात्रियों को प्राथमिक उपचार की दृष्टि से प्राथमिक चिकित्सा एवं वाहनों की पार्किंग, यातायात व्यवस्था तथा खोया पाया केंद्र बनाने, एम्बुलेंस एवं पेट्रोलिंग वाहन को तैयार रखने, क्षतिग्रस्त जालियों को व्यवस्थित करने सीढी मार्ग में दुकान लगाना प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गये। उन्होने कहा कि नवरात्रि मेले जैसे बड़े आयोजन की सफलता के लिये सभी अधिकारी-कर्मचारी पूरी ईमानदारी के साथ ड्यूटी करें। आपसी समन्वय के साथ काम करें और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर अपने उच्च अधिकारी को इसकी सूचना दें। कलेक्टर ने कहा कि नवरात्रि मेले के दौरान बंधा वैरियल से सभी के लिए दो पहिया और चार पहिया वाहन प्रतिबंधित रहेंगे बंधा बेरियल से अंदर आने के लिए सभी लोग ई-रिक्शा का प्रयोग करेंगे, केवल आवश्यक सेवा जैसे एंबुलेंस, दमकल, विद्युत सुधार वाहन, सफाई वाहन एवं पानी के टैंकर को अंदर जाने की अनुमति रहेगी।

पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल ने कहा कि 22 सितंबर से नवरात्रि मेला प्रारंभ होगा। इसके पहले मंदिर परिसर में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे रिपेयर कर आवश्यक सुधार कर लिया जाये। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों की संख्या भी बढाई जानी चाहिए।

ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन के लिए विशेष अभियान आज तक

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय संगठित व असंगठित क्षेत्रों के साथ-साथ सभी श्रेणियों के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी वितरण के लिए एक डेटाबेस ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से तैयार किया जा रहा है।

शासन द्वारा गिग/प्लेटफार्म वर्कस जैसे जोमेटो, स्विगी, ईंट श्योर, फूड पांडा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बिग बॉस्केट, ग्रोफर, जेप्टों, ब्लिंकिट, बेस्ट प्राइस, मेट्रो, डी-मार्ट, ओला, उबर, जुगनू, रेपिडो आदि में कार्य करने वाले ऐसे कर्मचारियों को इस श्रेणी के श्रमिकों को संबल योजना से जोड़ा गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में गिग/प्लेटफार्म वर्कस को कवर करने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के विस्तार की घोषणा की गई है। इसके अलावा उन्हें ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा और पहचान पत्र प्रदान किए जाएंगे। श्रम पदाधिकारी प्रिया अग्रवाल ने बताया कि गिग / प्लेटफार्म वर्कस के ई-श्रम पोर्टल तथा संबल पोर्टल पर पंजीयन के लिए 5 सितम्बर तक विशेष पंजीकरण अभियान चलाया जा रहा है। पंजीयन ऑनलाइन लिंक के माध्यम से स्वयं रजिस्ट्रेशन कर सकते है।

पुलिस गृह निर्माण समिति की सदस्यता सूची पर आपत्ति 12 सितम्बर तक

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। मध्यप्रदेश पुलिस गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित नवीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल के संचालक मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन किया जा रहा है। इस संबंध में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विकास माठे ने बताया कि समिति के संचालक मण्डल के सदस्यों के निर्वाचन और विशेष साधारण सम्मिलन के लिए समिति की सदस्यता सूची तैयार की गई है।

इस सूची का प्रकाशन समिति के कार्यालय के नोटिस बोर्ड, सहायक पंजीयक सहकारी समिति कार्यालय रीवा तथा विकासखण्ड कार्यालय जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रीवा शाखा के सूचना पटल पर कर दिया गया है। सूची के संबंध में दावे-आपत्तियाँ 12 सितम्बर तक समिति कार्यालय अथवा उपायुक्त सहकारिता में दर्ज की जा सकती हैं। प्राप्त दावे-आपत्तियों का निराकरण 13 सितम्बर को दोपहर 12 बजे से समिति कार्यालय में किया जाएगा। आपत्तियों के निराकरण के समय भी आपत्ति दर्ज करने वाले व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं।

एकीकृत आपातकालीन सेवा की शुरुआत, 9 डायल 112 वाहन मिले; एक नंबर पर पुलिस से लेकर एंबुलेंस तक की सुविधा

मीडिया ऑडीटर, मऊगंज (निप्र)। जिले में आपातकालीन सेवाओं को एकीकृत करने की पहल शुरू हो गई है। कलेक्टर संजय कुमार जैन और पुलिस अधीक्षक आर.एस. प्रजापति ने गुरुवार को दोपहर 3 बजे कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने से डायल 112 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले के पांच थानों में कुल 9 डायल 112 वाहन भेजे गए हैं। मऊगंज, हनुमना और शाहपुर थाने को दो-दो वाहन मिले हैं। लौर थाने को दो और नईगढ़ी को एक वाहन दिया गया है। एसपी आर.एस. प्रजापति ने बताया कि पुरानी डायल 100 सेवा को अपग्रेड करके डायल 112 बनाया गया है। नई सेवा में दो प्रमुख बदलाव किए गए हैं। हर वाहन में कैमरा, जीपीएस, स्ट्रेचर और आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। इससे पुलिस टीम घटनास्थल पर जल्दी पहुंच सकेगी। अब सभी आपातकालीन सेवाएं एक ही नंबर से जुड़ गई हैं। पहले महिला अपराधों के लिए 1095, अग्निशमन सेवा के लिए 108 और जननी सुरक्षा के लिए अलग नंबर डायल करने पड़ते थे।

अब सिर्फ 112 डायल करने से सभी सेवाएं मिल जाएंगी। स्टाफ के आचरण पर नजर रखने की विशेष व्यवस्था की गई है। इससे पुलिसकर्मी और जनता के बीच अनुचित व्यवहार पर रोक लगेगी। यह कदम जिले में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और आपात सेवाओं को सुगम बनाने में मदद करेगा।

टूटी पुलिया के कारण समय पर नहीं पहुंची एम्बुलेंस, इलाज के दौरान महिला की मौत; खाट पर शव रखकर लाया गांव

मीडिया ऑडीटर, मऊगंज (निप्र)। जिले में टूटी पुलिया के कारण एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाई। जिससे एक आदिवासी महिला की जान चली गई। पतेरी नारायण गांव की 38 साल की नीतू कोल पांच दिनों से बीमार थीं। इलाज के दौरान बुधवार को उसकी की मौत हो गई। गांव से मुख्य सड़क तक पहुंचने का रास्ता बारिश और कीचड़ के कारण बंद था।

5 दिन से बीमार थी महिला, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई: परिवार ने कई बार सोचा कि उन्हें अस्पताल ले जाए, लेकिन गांव से मुख्य सड़क तक पहुंचने का रास्ता बारिश और कीचड़ के कारण पूरी तरह बंद हो गया था। पुलिया टूटी होने से आवाजाही बाधित था और एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकी।

खाट पर डालकर ले जाना पड़ा अस्पताल: हालत बिगड़ने पर 30 अगस्त को परिजन नीतू को खाट पर लिटाकर 2 से 3 किलोमीटर तक पैदल चले और फिर पक्की सड़क पर पहुंचे। वहां से एम्बुलेंस के जरिए उन्हें मऊगंज और बाद में संजय गांधी अस्पताल, रीवा रेफर किया गया। डॉक्टरों ने भर्ती कर इलाज शुरू किया। इलाज के दौरान बुधवार को उसकी की मौत हो गई।

शव को भी खाट के सहारे लाया गया गांव: मौत के बाद भी हालात नहीं बदले। अस्पताल से शव लेकर जब परिजन गांव लौटे तो एम्बुलेंस मुख्य सड़क तक ही आ सकी। मजबूरन परिजनों को फिर खाट का सहारा लेना पड़ा और शव को पैदल गांव तक पहुंचाना पड़ा।

गांववासियों का कहना है कि वे चांद पर पहुंचने की बातें तो सुनते हैं, लेकिन अपने ही गांव तक पहुंच पाना आज भी संभव नहीं है। यह घटना न सिर्फ सिस्टम की लापरवाही को उजागर करती है बल्कि यह सवाल भी खड़ा करती है कि आखिर क्यों आदिवासी और दूरदराज के गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं।

सीएम दौरे से पहले पर्यटन स्थलों को कायाकल्प किया: विडंबना यह भी है कि जहां मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 7 सितंबर को मऊगंज जिले के दौरे पर आने वाले हैं, वहां तैयारी के लिए बहुती जलप्रपात और देवतालाब इलाके का कायाकल्प कर दिया गया। टूटे-फूटे भवनों को रेस्ट हाउस में बदल दिया गया और चुटकियों में हेलीपैड भी बना दिया गया।

आईटीआई में प्रवेश के लिए महिलाओं को विशेष अवसर

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। संभाग में संचालित 25 आईटीआई संस्थानों में विभिन्न ट्रेड्स में महिलाओं को प्रवेश के लिए विशेष अवसर दिए जा रहे हैं। महिलाओं का प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान में कालेज लेवल काउंसलिंग का का छठवां चक्र तथा इसके बाद सातवां चक्र चलाया जाएगा।

इस संबंध में प्राचार्य आईटीआई एसएन मिश्रा ने बताया कि संभाग में रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज तथा मैहर जिलों में संचालित आईटीआई में महिलाओं के प्रवेश के लिए स्थान उपलब्ध हैं। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के साथ महिलाएं अपने निकटतम आईटीआई में आवेदन करके निर्धारित ट्रेडों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकती हैं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर महिलाओं को प्रवेश दिया जाएगा।

हाईवे पर लूट करने वाले 5 बदमाश गिरफ्तार, 1 फरार; कट्टा और कारतूस भी बरामद

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। पुलिस ने हाईवे पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने छतरपुर के व्यापारी से कट्टा दिखाकर मोबाइल फोन और नगदी लूटी थी। साथ ही उसके फोन पे अकाउंट से हजारों रुपये ट्रांसफर कर लिए थे। घटना 2 सितंबर की है। छतरपुर निवासी शिवकुमार गुप्ता सतना से पशु आहार लेकर पिकअप वाहन से लौट रहे थे। लोटस सिटी के पास उनकी गाड़ी खराब हो गई। वे सड़क किनारे वाहन में सो गए। रात करीब 3:45 बजे दो मोटरसाइकिलों पर सवार छह बदमाशों ने कट्टा दिखाकर उनसे मोबाइल फोन और 1 हजार रुपए नगद छीन लिए। आरोपियों ने फोन पे अकाउंट से 5 हजार 620 रुपए भी ट्रांसफर कर लिए।

5 आरोपी गिरफ्तार, एक फरार: पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता के निर्देशन में विशेष टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की। पुलिस ने विक्कू कुशवाहा, ऋतिक तिवारी उर्फ रिशु, मनीष दहिया, दीपू दहिया और शिवम पटेल को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी रोहित तिवारी अभी फरार है।

बरामद सामान की कीमत करीब ढाई लाख रुपए: पुलिस ने आरोपियों से 315 बोर का देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, दो मोटरसाइकिल और पांच मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामद सामान की कीमत करीब ढाई लाख रुपए है। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। फरार आरोपी की तलाश जारी है।

जबलपुर एयरपोर्ट से पकड़ाए आरोपी की जमानत खारिज

धर्म छिपाकर युवती को भगाने का मामला, सतना में कोर्ट ने कहा- अपराध गंभीर

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। धार्मिक पहचान छिपाकर युवती को शादी के लिए मजबूर करने के मामले में एससी-एसटी एक्ट की स्पेशल कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट से पकड़े गए आरोपी शहनवाज हुसैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। विशेष न्यायाधीश प्रशांत कुमार निगम ने अपराध की प्रकृति और धर्म परिवर्तन की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया। आरोपी शहनवाज हुसैन जवान सिंह कॉलोनी का रहने वाला है।

जबलपुर एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुआ आरोपी: मामले के अभियोजन पक्ष के जीपी रमेश मिश्रा के अनुसार, पीड़िता के पिता ने 28 अगस्त 2025 को सिटी कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच में पता चला कि आरोपी युवती को बहला-फुसलाकर दिल्ली ले जा रहा था। पुलिस ने आरोपी को जबलपुर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर युवती को उसके परिवार को सौंप दिया।

पुलिस ने उसे झूठे मामले में फंसाया: पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 351(2) और मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3/5 के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी का दावा है कि उसने शादी का दबाव नहीं डाला और युवती से उसकी मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई थी। उसका कहना है कि पुलिस ने उसे झूठे मामले में फंसाया है।

संभाग में हुई 9.96 लाख हेक्टेयर में फसलों की बुवाई अच्छी वर्षा से संभाग में लक्ष्य से दो प्रतिशत अधिक हुई बुवाई

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। संभाग के सभी जिलों में इस वर्ष जून माह से ही अच्छी वर्षा होने के कारण खरीफ फसल की लक्ष्य से अधिक बुवाई हुई है। इस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य 9.92 लाख हेक्टेयर के विरूद्ध 9 लाख 96 हजार 780 हेक्टेयर में खरीफ फसल की बुवाई हुई है। खरीफ की मुख्य फसल धान है। धान के लिए निर्धारित लक्ष्य 6 लाख 98 हजार हेक्टेयर के विरूद्ध संभाग में 7 लाख 12 हजार 600 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की बुवाई की गई है।

इस संबंध में संयुक्त संचालक कृषि केएस नेताम ने बताया कि हाल ही में अच्छी वर्षा से धान सहित सभी फसलों की लक्ष्य से अधिक बुवाई हुई है। संभाग में 8400 हेक्टेयर में ज्वार, 17850 हेक्टेयर में मक्का, 1500 हेक्टेयर में बाजरा, 28400 हेक्टेयर में कोदौ-कुटकी की बोनी हो चुकी है। दलहनी फसलों में 59630 हेक्टेयर में अरहर, 31050 हेक्टेयर में मूंग, 71360 हेक्टेयर में उड़द की बोनी हो चुकी है। तिलहनी फसलों में 63190 हेक्टेयर में तिल तथा 2900 हेक्टेयर में सोयाबीन बोया गया है।

समन्वय बनाकर सुचारू ढंग से खाद वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करें : डॉ. सौरभ सोनवणे

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। प्रभारी कलेक्टर डॉ सौरभ सोनवणे ने गूगल मीट के माध्यम से जिले में खाद वितरण के लिए समन्वय बनाते हुए सुचारू ढंग से व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने एसडीएम, तहसीलदार व कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले को प्राप्त होने वाली खाद का डबल लाक के माध्यम से 8 सितम्बर से वितरण किया जाएगा। जबकि सेवा सहकारी समितियों में उपलब्ध होने वाली खाद का वितरण शनिवार 6 सितम्बर व रविवार 7 सितम्बर को भी किया जाएगा।

कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार से गूगल मीट के माध्यम से जिले में खाद वितरण की व्यवस्थाओं के संबंध में की गई तैयारियों की प्रभारी कलेक्टर ने जानकारी प्राप्त की तथा निर्देश दिए कि सभी एसडीएम अपने क्षेत्र में खाद वितरण के लिए व्यवस्थाओं के संबंध में स्थानीय स्तर पर प्रचार माध्यमों से किसानों को अवगत कराएं। उपलब्ध खाद के साथ ही टोकन वितरण की व्यवस्था तथा अन्य जानकारियाँ स्थानीय स्तर पर इन माध्यमों से किसानों को दें। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों एवं किसान संगठनों से समन्वय बनाकर खाद का व्यवस्थित वितरण सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि सेमरिया व मनगवां में इफको ई बाजार में खाद की उपलब्धता कराई जा रही है। यहाँ से भी किसान खाद प्राप्त कर सकेंगे। बैठक में एसडीएम हुजूर वैशाली जैन, एसडीएम गुढ़ डॉ अनुराग तिवारी, तहसीलदार हुजूर शिवशंकर शुक्ला, जिला विपणन अधिकारी शिखा वर्मा, उप संचालक कृषि यूपी बागरी तथा महाप्रबंधक केन्द्रीय सहकारी बैंक ज्ञानेन्द्र पाण्डेय उपस्थित रहे।

नगर परिषद पहुंची कंगाली की ओर कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा है हर माह वेतन

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। इस समय त्योंथर क्षेत्र की दो नगर परिषद् त्योंथर एवं चाकघाट कंगाली के कगार पर पहुंच रही हैं जिसके चलते यहां कार्यरत कर्मचारियों को प्रतिमाह निर्धारित समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है और न ही नगर परिषद के द्वारा जनहित में छोटे-मोटे कार्य कराए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार पूर्व में नगर परिषद को मध्य प्रदेश शासन द्वारा चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान की जाती थी जिस राशि से नगर परिषद के कर्मचारियों को वेतन दिया जाता था किंतु इधर लंबे समय से शासन द्वारा दिए जाने वाली चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि से विद्युत बिलों के भुगतान एवं नगर परिषद द्वारा विकास कार्यों के लिए के लिए दिए गए कर्ज की किस्त ऊपर से ही काट कर शेष राशि नगर परिषद को में भेजी जा रही है। कटौती के पश्चात यह राशि इतनी कम हो जाती है कि कर्मचारियों का वेतन मिल पाना मुश्किल हो जाता है। इतना ही नहीं पैसे के अभाव में कुछ स्थानों पर कर्मचारियों के वेतन से कटौती करके जो राशि भविष्य निधि खाते में जमा होनी चाहिए वह राशि भी लंबे समय से उनके खाते में जमा नहीं हो पा रही है, जबकि वेतन से वह राशि काट ली जा रही है।

नगर परिषद में आए दिन कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जा रही है प्रत्येक अध्यक्ष द्वारा अपने कुछ चहेतों को कार्यालयीन कार्य एवं व्यवस्था के नाम पर रख लिया जाता है और बाद में इनकी संख्या हर 5 वर्ष में नए अध्यक्ष के कार्यकाल के साथ ही बढ़ती जाती है जिनको दिए जाने वाला वेतन का भार भी नगर परिषद को पड़ता है। आमदनी के स्रोत नगर परिषद क्षेत्र में नहीं बढ़ पा रहा है ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। मध्य प्रदेश शासन से आग्रह है कि आर्थिक मामलों में बदहल हो रहे नगर परिषद के कर्मचारियों को वेतन हेतु कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाय जिससे उन्हें हर महीने वेतन का भुगतान प्राप्त हो सके तथा उनके वेतन से होने वाली भविष्य नीति कटौती भी भविष्य निधि खाते में निर्धारित समय पर जमा हो सके।

स्वत्वाधिकारी मुद्रक/प्रकाशक संदीप द्विवेदी द्वारा मीडिया ऑडीटर पब्लिकेशन प्रा.लिमि. राजीव मार्ग निराला नगर रीवा से मुद्रित कर मीडिया ऑडीटर कार्यालय राजीव मार्ग निराला नगर रीवा से प्रकाशित, **संपादक संदीप द्विवेदी**, आर.एन.आई नं. 69082/97, डाक पंजीयन क्र.- म. प्र./ रीवा संभाग/ 46/2023-2025, प्रधान कार्यालय रीवा (सिटी कार्यालय चक्रधर सिटी सेंटर रीवा) फोन. नं. 9589645803, 7974467831 Mediaauditor1@gmail.com सभी विवादों का न्याय क्षेत्र रीवा होगा।